



वर्तमान

कमल ज्योति







वर्तमान कमल ज्योति

संरक्षक

श्री स्वतंत्र देव सिंह

सम्पादक

अरुण कान्त त्रिपाठी

प्रबन्ध सम्पादक

राजकुमार

प्रकाशक

प्रो० श्याम नन्दन सिंह

पृष्ठ संयोजक

ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय

कमल ज्योति, 7-विधानसभा मार्ग

लखनऊ - 1

फोन :- 0522-2200187

फैक्स :- 0522-2612437

Email-

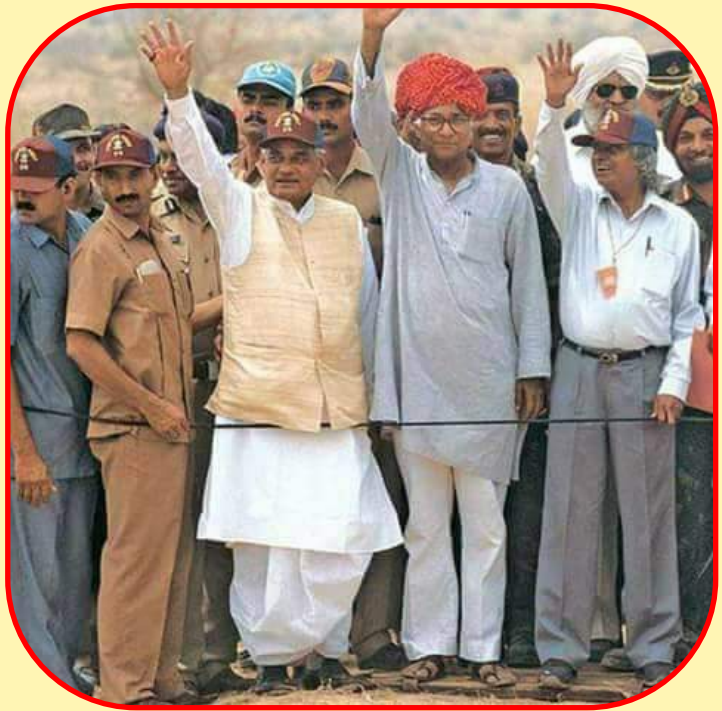
bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से
सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक

नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र,
राजेन्द्र नगर, लखनऊ-4

राष्ट्रीय तकनीक दिवस



राष्ट्रीय तकनीक दिवस (National Technology Day) पर सभी को अशेष शुभकामनाएं। आज के ही दिन भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंकाने का काम किया था।

अपने उन महान वैज्ञानिकों और इस अभियान लगे सभी व्यक्तियों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने दुनिया की नजरों से छिपते छिपाते इस परीक्षण को सफलतापूर्वक लक्ष्य तक पहुंचाया। साथ ही साथ हम गर्व के साथ अटल जी के अनुकरणीय नेतृत्व को याद करते हैं जिन्होंने उत्कृष्ट राजनीतिक साहस और राज्य कौशल दिखाया। उन्होंने ने बता दिया था कि भारत किसी से भी डरने और झुकने वालों में से नहीं है।

11 मई 1998 को पोखरण में भारत ने ये परीक्षण दोपहर 15:45 बजे किया था। इस परीक्षण की खास बात ये थी कि इसकी खबर अमेरिका को भी तब लगी थी जब ये हो चुका था। इतना ही नहीं अमेरिका ने भारत की निगरानी के लिए अपनी सेटेलाइट का रुख भी इधर ही किया हुआ था। इसके बाद भी वो इसकी जानकारी नहीं पा सका था।

भारतीय प्रतिभाओं को कोटिशः नमन।

देश समाज के लिये जीता है भाजपा कार्यकर्ता

अधिष्ठानं तथा कर्त्ता करणं च पृथग्विधम् ।

विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम् ॥

कर्मसिद्धि के लिये अधिष्ठान, कर्ता अनेकाविध साधन अनेक प्रकार की चेष्टाएं और पांचवां देव ये पांच लक्षण एक कार्यकर्त्ता में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा संगठन की प्रेरणा, उसका सैद्धांतिक आधार, उसका ध्येय संकल्प और ध्येयपूर्ति तक ले जाने वाला ऊर्जा स्रोत और उसका गंतव्य मिलकर संगठन को प्रतिदिन एक आधार प्रदान करते हैं। कार्यकर्त्ता का यह आधार और उसका वैचारिक अधिष्ठान भाजपा को उसके उच्चतम शिखर तक लेकर जा रहा है। इसको यदि हम दूसरी दृष्टि से देखें तो पाते हैं कि, भाजपा कार्यकर्त्ताओं के युग्म की वह संचयिता है जिसके कारण ही भाजपा अपने आधार को प्रतिस्थापित करती है। इतना ही नहीं भाजपा का कार्यकर्त्ता भाजपा को चलाने, उसको गतिमान बनाने और उसके उच्चतम मानदंडों की प्रतिपूर्ति करने में भी सहायक होता है। इसको समझने के लिये उत्तर प्रदेश में चुनाव के तुरंत बाद चलने वाले उन अभियानों से समझ सकते हैं जिसके लिये प्रत्येक कार्यकर्त्ता बिना थके अपने कार्य में संलग्न रहा है। भाजपा के लिये उसके अंशदान को इसके लिये एक उदाहरण माना जा सकता है। एक महीने के माइक्रो डोनेशन में भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्त्ता ने दिनरात पार्टी को संबल प्रदान किया है।

भाजपा के कार्यकर्त्ता के रूप में हर कार्यकर्त्ता ने न केवल अपना अंशदान दिया अपितु पार्टी के साथ दूसरों को जोड़कर उनका भी अंशदान कराया। ऐसा विश्व में किसी संगठन में नहीं पाया गया है। माइक्रो डोनेशन के साथ ही कार्यकर्त्ताओं ने स्वयं को गढ़ने के लिये पार्टी द्वारा प्रत्येक जिले में आयोजित तीन दिन के प्रशिक्षण शिविर में भी भाग लिया। जबकि उस दौर में हर परिवार में विवाह समारोहों की भरमार रही लेकिन हमारे देवतुल्य कार्यकर्त्ताओं ने अपने प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी। कार्यकर्त्ता व्यवहार का यह ऐसा अनूठा चरण है जिसकी प्रतिपूर्ति के लिये कोई संगठन आधार नहीं तैयार कर सकता है। भाजपा में यह आधार उसके वैचारिक अधिष्ठान का अभूतपूर्व अंग है। इसी आधार को पकड़कर भाजपा का कार्यकर्त्ता प्राण-प्रण से पार्टी के प्रत्येक अभियान में लगता है और अभियान को सफल बनाकर स्वयं को संतुष्ट पाता है। उसका अपना कोई कार्य पूरा नहीं होता लेकिन वह कार्यकर्त्ता पूरी निष्ठा ईमानदारी और संपूर्ण समर्पण के साथ अभियान को समाज के बीच उदाहरण बना देता है। हमारा कार्यकर्त्ता हमेशा नाराज रहता है। वह हमेशा अपने अधिकारियों के प्रति गुस्सा दर्शाता है लेकिन जैसे ही संकट काल को महसूस करता है बिना बुलाये समाज के बीच पार्टी को स्थापित करने में जुट जाता है।

मुझे याद है कि 2017 के विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद बिना थके भाजपा कार्यकर्त्ता निकाय के चुनावों में संलग्न हो गया। उसके बाद सरकार की गतिविधियों को लेकर समाज के हर वर्ग तक जाकर प्रचार-प्रसार में जुट गया। 2019 के लोकसभा चुनावों तक बिना थके पार्टी के हर कार्य हर आंदोलन हर चेतना की लेकर जुटा रहा है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है इसा प्रत्यक्ष अनुभव नीचे के कार्यकर्त्ता ने आत्मसात किया लेकिन उसको अनुभव नहीं किया। लोकसभा चुनावों में उसकी प्रतिबद्धता के सहारे पार्टी ने अभूतपूर्व विजय को वरण किया। हमारा कार्यकर्त्ता संभला भी नहीं था कि कोबिड की दस्तक ने हर किसी को प्रभावित कर लिया। प्रदेश का स्वनिष्ठ कार्यकर्त्ता अपने प्राणों की परवाह किये बिना पार्टी के ण्क आह्वन पर सड़को पर निकल पड़ा। हर किसी को सहायता को तत्पर कार्यकर्त्ता ने सुदूर प्रदेशों से आने वालों के पगों में पनही पहनाने का कार्य किया। कोबिड के साथ ही प्रदेश के विधानसभा चुनावों में डूबकर लगा और भाजपा की लगातार दूसरी बार सत्ता की दहलीज तक लेकर आया। इस बीच उसको न सत्ता का रंग चढ़ा न सत्ता की राजसत्ता का अनुभव हुआ। लेकिन उसके मनागत में केवल पार्टी को दूसरी बार प्रदेश में स्थापित करने का था और उसने अपने मनोगत को तमाम झंझावतों के बीच से निकालकर प्रतिस्थापित कर दिया। विधानसभा चुनावों दो महीने के अंदर ही पार्टी के लिये प्राण-प्रण से जुटा और अपने शिखर को और आलोकित करने का कार्य किया। वह ऐसा इसलिये कर सका क्यों कि वह ईमानदार है। राजनीति के अंदर रहकर कमल को खिलाने का हुनर जानता है। वह स्वयं के लिये नहीं समाज के लिये जीता है। वह कर्तव्यनिष्ठ है। ईमानदार है। चरित्रवाला है। दलाली उसके चरित्र में नहीं है। समान के प्रत्येक अनु को वह साकार करता है। उसके चरित्र पर उसकी निष्ठा पर उसके ईमान पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ... आप भी नहीं!

akatri.t@gmail.com

सरकार की नीतियों से राहत में आम आदमी

अरुण कान्त त्रिपाठी

दिसंबर में पहली बार ऐसा हुआ कि देश में महंगाई दर में अचानक बढ़ोतरी होती रही है। इसके पूर्व नवंबर से लेकर जनवरी के मध्य में महंगाई स्थिर रहा करती थी। लेकिन इस सबके बीच केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों ने लोगों को भारी राहत प्रदान की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना काल की तरह यूक्रेन संकट से बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार की आर्थिक-सामाजिक योजनाओं से देश के करोड़ों परिवारों को राहत मिलती दिखी है। यूक्रेन संकट की वजह से महंगाई को देखते हुए विगत दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने सितंबर 2022 तक 80 करोड़ आबादी को मुफ्त में राशन देने का फैसला किया है।

यह कोई छोटी बात नहीं है कि, देश में जनधन, आधार और मोबाइल के कारण आम आदमी डिजिटल दुनिया से जुड़ गया है। एकीकृत बुनियादी डिजिटल ढांचा विकसित हुआ है, वह आम आदमी की आर्थिक-सामाजिक मुस्कुराहट का आधार बना है। यदि हम केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का मूल्यांकन करें, तो अधिकांश

योजनाएं राजकोषीय घाटा बढ़ाने का कारण नहीं बन रही हैं। वे आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण का काम कर रही हैं। ऐसी योजनाओं में एलपीजी गैस सब्सिडी, शौचालय निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, नल जल कनेक्शन, महामारी के दौरान निःशुल्क अनाज वितरण, निशुल्क कोरोना टीकाकरण, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पोषण कार्यक्रम, ई-रूपी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, स्टैंड अप इंडिया और अटल पेंशन आदि शामिल हैं। किसानों के लिए लागू कल्याणकारी योजनाओं ने कृषि क्षेत्र को नई मुस्कुराहट दी है। इसके अलावा निजी क्षेत्रों द्वारा भारी मात्रा में गेहूं की खरीद से किसानों को बड़ा लाभ हो रहा है।

लेकिन, इन मुस्कुराहटों के बीच देश में राजनीतिक संकट का एक दूसरा पहलू कुछ राज्य सरकारों द्वारा मुफ्त दी जा रही योजनाओं से खड़ा हो रहा है। दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सरकारों द्वारा घोषित लोकलुभावन योजनाओं और मुफ्त रियायतों पर चिंताएं जाहिर करते हुए कहा कि ऐसी योजनाएं और

रियायतें आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बैठक में शामिल उच्च अधिकारियों ने देश में कई राज्यों द्वारा दी जा रही रियायतों को कई श्रीलंका की तरह आर्थिक मुश्किलों के रास्ते पर ले जाने वाला करार किया है। श्रीलंका में पिछले कुछ समय से लागू की गई लोकलुभावन योजनाओं, करों में भारी कटौती और बढ़ते कर्ज ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को सबसे बुरे दौर में पहुंचा दिया है। 2018 में वैट की दर 15 फीसदी से घटाकर 8 फीसदी की गई और विभिन्न वर्गों को दी गई अभूतपूर्व सुविधाओं व छूटों के कारण श्रीलंका दर्दनाक मंदी और चीन के ऋण जाल में फंस गया है। श्रीलंका में इस साल महंगाई दर एक दशक में अपने सर्वाधिक स्तर पर पहुंच चुकी है। आर्थिक तंगी के खिलाफ तेज होते विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार को आपातकाल करना पड़ा। इतना ही नहीं श्रीलंका के द्वारा मौजूदा विदेशी मुद्रा संकट से निपटने में मदद करने के लिए भारत से आर्थिक राहत पैकेज का आग्रह किया गया है जिस पर हमारी

**विकास के पथ पर बढ़ता प्रदेश
ये है नए सपनों का उत्तर प्रदेश**

**इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में
यूपी को 1 स्थान**

Smart City
MISSION TRANSFORM NATION



**देश के गरीब परिवारों को गरिमामय
जीवन देने हेतु**

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

**के तहत सामाजिक सुरक्षा
प्रदान कर रही है
केंद्र सरकार**



- **28.37 करोड़ लोगों ने कराया पंजीकरण**
- **97,220 दावों का किया गया भुगतान**
- **₹1,930 करोड़ की धनराशि की गई निर्गत**



साथ ही केन्द्र सरकार ने विकास के लिए कठोर फैसलों की भी रणनीति अपनाई है, उससे आर्थिक मुश्किलों का सामना करते हुए देश विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 के बाद अब रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच बढ़ती महंगाई मद्देनजर जहां आम आदमी के आर्थिक – सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाओं से लोगों की आर्थिक मुश्किलें कम करके उनके सशक्तिकरण का लक्ष्य रखा है, वहीं सरकार जीएसटी और आयकर में भारी रियायतों से दूर रही है। परिणामस्वरूप कोविड-19 के बाद लगातार टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है और देश आर्थिक पुनरुद्धार की डगर पर आगे बढ़ रहा है।

रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई से आम आदमी को राहत दिलाने में देश की कल्याणकारी

सरकार कार्य कर रही है।

लोकलुभावन योजनाओं और विभिन्न कर छूटों के कारण श्रीलंका आर्थिक बर्बादी की तरह ही देश में उन राज्यों की सरकारों की योजनाएं एक उदाहरण बन रही हैं जिससे उन प्रदेशों की अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं विभिन्न वर्गों के लिए मुफ्त यात्रा, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी या फिर नाम मात्र की दर पर ढेर सारी सुविधाएं देने वाले विभिन्न राज्यों में लोगों की कार्यशीलता और उद्यमिता में भी कमी आई है। साथ ही ऐसे प्रदेश चुनौतीपूर्ण राजकोषीय घाटे की स्थिति में आ गए हैं और वहां बुनियादी ढांचा और विकास बहुत पीछे हो गया है। इन राज्यों में दिल्ली, पंजाब, केरल, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के नाम प्रमुख हैं। यदि हम देश में राजकोषीय घाटे के दलदल में पहुंच चुके विभिन्न राज्यों के द्वारा अपनाई गई मुफ्त सुविधाओं और योजनाओं के साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अपनाई गई कल्याणकारी योजनाओं की तुलना करें तो बड़ा अंतर दिखाई देता है। मोदी सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, उनसे लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। गरीब वर्ग की कार्यक्षमता बढ़ने के साथ उनकी आमदनी से वृद्धि हो रही है। इसके

योजनाएं अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रही हैं तथा देश को आत्मनिर्भरता की डगर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही सरकार उपयुक्त रणनीति के साथ राजस्व में भी वृद्धि कर रही है। देश में सरकारी तेल विपणन कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के मूल्यों के आधार पर पेट्रोल व डीजल की कीमतों में धीरे-धीरे वृद्धि की नीति पर चल रही है। देश में आर्थिक और सामाजिक कल्याण की विशाल योजनाओं के लागू होने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था एक बड़े आर्थिक पुनरुद्धार की ओर जा रही है। ज्यादा जीएसटी संग्रह के साथ ही सीमा शुल्क और प्रत्यक्ष कर संग्रह में इजाफा होने से सरकार का सकल कर राजस्व वित्त वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान से अधिक दिखाई दे रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2021-22 में करीब 9 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। हमें उम्मीद है कि हमारे ऐसे राज्य जो लोकलुभावन योजनाओं व ढेर सारी रियायतों के प्रतीक बन गए हैं, वे सबसे बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे श्रीलंका से सबक लेंगे।

देवभूमि की सांस्कृतिक पहल



अलकनंदा पर्यटक आवास उत्तराखंड को और भागीरथी पर्यटक आवासए उत्तर प्रदेश को मिल गया है। मैं इसके लिए उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ: योगी

भारतीय संस्कृति में माँ की महिमा अपरम्पार है। वर्षों बाद योगी आदित्यनाथ जी तीन दिवसीय देवभूमि के प्रवास पर रहे वहाँ बहुत दिनों बाद अपने पैत्रिक गाँव गये। अपनी माता जी के साथ गाय, गंगा, गौरी के दर्शन किये। अपने पूर्व परिचित, परिजनों से भेंट किया। इसी प्रवास में उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड सरकार के बीच वर्षों लम्बित पड़े कई समस्याओं का समाधान हुआ। देवभूमि हरिद्वार में सांस्कृतिक महत्व की हरिद्वार अनेक यात्रा, कार्यक्रमों में जन सुविधा की दृष्टि से भागीरथी पर्यटक आवासगृह हरिद्वार के लोकार्पण कार्यक्रम में मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ सम्पन्न हुआ।

हरिद्वार में पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए उ0प्र0 सरकार द्वारा भागीरथी पर्यटक आवासगृह का निर्माण 4326.96 लाख रुपये की धनराशि से कराया गया है। इस पर्यटक आवास में 100 कक्षों का निर्माण कराया गया है। इसमें 10 वातानुकूलित, 90 डबल बेड कमरे, वातानुकूलित रसोई घर, बैंकवेट हॉल तथा 150 चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गयी है। इस आवास से गंगनहर के घाट एवं हरि की पैड़ी पर सीधे पहुंचने की व्यवस्था है। इन भवनों में आदान प्रदान से सांस्कृतिक सम्बन्धों में और मधुरता आयी है।

विकास की नई इबारत.... योगी सरकार!

मीना चौबे



उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। सूबे की जनता ने पिछले पांच साल के काम को देखते हुए योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा सत्ता पर बिठाया है। वहीं योगी आदित्यनाथ जी ने भी सत्ता संभालते ही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर खरा उतर कर योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम बनाने के लिए दिन रात एक कर दिये हैं।

वहीं आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूत करने के लिए स्थानीय उत्पादों के संरक्षण और उनको प्रोत्साहित करने के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर उत्तर प्रदेश के नागरिकों से स्वदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काम में लापरवाही को लेकर प्रदेश के पुलिस प्रमुख मुकुल गोयल को उनके पद से हटा दिया है। प्रदेश सरकार के एक आधिकारिक बयान में इसकी तस्दीक की गई है। इसमें कहा गया है कि उन्हें डीजीपी के ओहदे से

हटाकर नागरिक सुरक्षा विभाग का महानिदेशक (डीजी) बनाया गया है। गोयल को आधिकारिक कार्यों की उपेक्षा और विभागीय कार्यों में रुचि नहीं लेने के कारण डीजीपी के पद से हटा दिया गया था।

साथ ही यूपी सरकार ने राज्य के 5 शहरों में छोटे एयरपोर्ट विकसित किए जाने पर सहमति दे दी है, जिससे हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। इसके लिए यूपी सरकार ने 5 हवाईअड्डों के मेंटेनेंस के लिए एमओयू साइन किया है। इसके बाद अब अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र में एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे, जिसके मेंटेनेंस पर सरकार 7 करोड़ रुपये हर साल खर्च करेगी।

ललितपुर में 174.97 करोड़ की लागत से बन रही कचनौंदा बांध परियोजना के तहत 62 गांव के 1.45 लाख ग्रामीणों को नल से पेयजल मिलेगा। इस परियोजना का कार्य 174 करोड़ की लागत से हो रहा है। जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश सरकार जमीनी स्तर पर तेजी से काम कर रही है। भूगर्भ जल को संजोने के लिए जहां गांव गांव में तेजी से

तलाबों का जीर्णोद्धार और निर्माण किया जा रहा है वहीं योगी सरकार प्रदेश में तेजी से नए कूप, नए बांधों का निर्माण करा रही है।

मिशन रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री प्रतिबद्ध है। मुख्य सचिव से सभी आयोगों की 100 दिनों में लक्ष्य के अनुरूप भर्ती की रिपोर्ट मांगी है। अद्यतन स्थिति की सभी आयोगों की समीक्षा कर रिपोर्ट देने और प्राथमिकता के आधार पर सभी रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने रिक्त पदों पर समयबद्ध चयन के लिए समय से अध्यापन भेजने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने सीधी भर्ती के लिए सभी विभागों द्वारा अध्यापन 31 मई से पहले भेजने के निर्देश दिये हैं। उत्तर प्रदेश में तीन दशक से बंद

पड़े आग्जिलरी नर्स मिडवाइफरी (एएनएम) और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) प्रशिक्षण केंद्र फिर शुरू जाएंगे। नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्षेत्र में युवाओं के लिए करियर की अच्छी संभावनाएं बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि मेडिकल कालेज और जिला अस्पतालों में भी इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। आपातकालीन एंबुलेंस सेवाओं के संचालन को भी और बेहतर करने पर जोर दिया है।

सरकार में रैपिड रेल का कार्य तेजी से चल रहा है। अब 14 लेन के एक्सप्रेसवे ने दिल्ली की दूरी कम कर दी है। जल्द गंगा एक्सप्रेस-वे और जेवर हवाई अड्डे से मेरठ की सूरत बदल जाएगी। मेरठ खेल उत्पादों को लेकर पूरी दुनिया में जाना जाता है। योगी सरकार यहां खेल विश्वविद्यालय भी बना रही है।

अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक जीतकर यूपी का मान



बढ़ाने वाले खिलाड़ियों की 24 राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती होगी। इसके लिए नौ विभागों के इन 24 पदों को यूपी लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगाई। फैसला एक सितंबर 2020 से लागू होगा। सरकार अन्नदाताओं की बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य में चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने संकल्प पत्रों में किसानों के लिए कई तरह की योजनाओं को लागू करने का वादा किया था। इसी कड़ी में सरकार 33,408 किसानों का कर्ज माफ करने की तैयारी में है। राज्य के कृषि विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव भेज रहा है।

मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में अब तक कोविड टीके की 31 करोड़ 85 लाख डोज लगाई जा चुकी है। 11 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड टेस्ट भी किए जा चुके हैं। 18 साल से अधिक आयु की पूरी आबादी को टीके की कम से कम एक डोज लग चुकी है, जबकि 89.86 फीसदी वयस्क लोगों को दोनों खुराक मिल गयी है।

वहीं 15 से 17 साल आयु वर्ग में 95.85 प्रतिशत से अधिक किशोरों को पहली खुराक मिल चुकी है और 69.80 प्रतिशत से अधिक किशोरों को दोनों डोज लग गयी है। 12 से 14 साल आयु वर्ग में 70 फीसदी से अधिक बच्चे टीका कवर पा चुके हैं। इन्हें दूसरे डोज लगाया जाना भी शुरू हो चुका है। इस तरह बच्चों के टीकाकरण और वयस्कों के बूस्टर डोज लगाए जाने की गति तेजी से चल रही है।



“वसुंधैव कुटुम्बकम्” की नई सुबह!

साधक राजकुमार

वैश्विक राजनीति में शांति, सौहार्द, समृद्धि, आरोग्यता की तलाश में दुनिया के लिए भारत आशा की किरण बनता जा रहा है। कोरोना, युद्ध, अशान्ति में भारत की वसुंधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा सबको लुभा रही है। आपदा काल में दुनिया के देशों को वैक्सीन, दवाईयां, परिवार भाव का स्नेह, योग, आयुर्वेद, शांति के प्रयासों की आज मोदी जी के पहल की दुनिया मुरीद होती जा रही है। प्रधानमंत्री की छोटी सी, लेकिन बेहद सफल विदेश-यात्रा ने भारत और यूरोप के बीच संबंधों को नई दिशा दी है। वह भी ऐसे मौके पर, जब यूरोप संकट से घिरा है और भारत के सामने रूस और अमेरिका के साथ रिश्तों को पारिभाषित करने की कोई दुविधा नहीं है। इससे पूर्व की सरकारों में स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत और यूरोप के रिश्ते असमंजस से भरे रहे हैं। एक अरसे से उम्मीद थी कि असमंजस का यह दौर कभी तो टूटेगा। अब पहली बार भारत ने यूरोप के साथ बेहतरीन रिश्तों की आधार-भूमि तैयार कर ली है। आर्थिक-राजनीतिक सहयोग, तकनीकी और वैज्ञानिक रिश्तों और भारत के सामरिक हितों के नजरिये से नए दरवाजे खुले हैं। इस घटनाक्रम के समानांतररूप पर लग रही पाबंदियों के प्रभाव को भी दूसरी तरह से समझना होगा। यूक्रेन का युद्ध अभी तार्किक-परिणति पर नहीं है। फिलहाल यूक्रेन एक विभाजित देश के रूप में बचेगा इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। यहां से वैश्विक-राजनीति का एक नया दौर शुरू होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी जी का यूरोप प्रवास

मोदी की यात्रा ने यूरोप के देशों के बीच भारत के संबंधों को नई दिशा दी है। आर्थिक राजनीतिक सहयोग, तकनीकी और वैज्ञानिक रिश्तों और भारत के सामरिक हितों के नजरिये से नए दरवाजे खुले हैं।

स्वतंत्र विदेश-नीति भारत की स्वतंत्र विदेश-नीति से जुड़ी बातें भी अब स्पष्ट हो रही हैं। पिछले 75 वर्षों में भारत ने कमोबेश वैश्विक घटनाचक्र से एक दूरी बनाकर रखी, पर अब वह भागीदार बनकर उभर रहा है। शीतयुद्ध के बाद भारत ने चीन और रूस के संभावित गठजोड़ के साथ जुड़ने का प्रयास भी किया, पर पिछले दो वर्षों में इस नीति पर भी गहन विचार हुआ है। अब हम अमेरिका, यूरोप और रूस-चीन के साथ विकसित होती बहुध्रुवीय दुनिया में स्वाभाविक पार्टनर के रूप में उभर कर आ रहे हैं। यूरोप के देशों ने भारत के आर्थिक-विकास में भागीदार

बनने का इरादा जताया है। यूरोप के उप-क्षेत्र समूचा यूरोप एक जैसा नहीं सोचता और न समूचे यूरोप के हित एक जैसे हैं। यूरोप में उप-क्षेत्रीय हितों को समझने की जरूरत भी है। भारतीय विदेश-नीति के निर्धारकों ने इस बात को समझा है।

भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाबत अपनी दृष्टि को यूरोपीय देशों के सामने सफलता के साथ स्पष्ट किया है और यूरोप के देशों ने उसे समझा है। भारत ने हमले की स्पष्ट निंदा नहीं की है, पर परोक्ष रूप से इस हमले को निरर्थक और अमानवीय माना है। अंधेसा था कि यूरोप के देश इस बात को पसंद नहीं करेंगे, पर पूरी यात्रा के दौरान भारत



और यूरोपीय देशों ने एक-दूसरे के हितों को पहचानते हुए, असहमतियों के बिंदुओं को रेखांकित ही नहीं किया बल्कि भारत के साथ राजनीतिक-आर्थिक संबंधों को एक नई दिशा भी दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस युद्ध से जुड़े मानवीय पहलुओं को लेकर आपसी सहयोग की संभावनाओं को रेखांकित किया। भारत ने स्पष्ट किया है कि हम तीनों पक्षों अमेरिका, यूरोप और रूस के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं। इससे यूरोपीय देश यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की नीति को समझ गए हैं। अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि भारत रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे, ताकि रूस की तरफ से युद्ध को समाप्त करने के लिए बात शुरू हो। यूक्रेन युद्ध पर भारत की दृष्टि यूरोप से अलग है। हमें यह भी स्पष्ट करना है कि हम रूस का साथ छोड़ेंगे नहीं। हमें रक्षा-सामग्री के लिए उसकी जरूरत है। अफगानिस्तान में सक्रिय रहने और चीन को काउंटर करने के लिए भी हमें रूस के साथ रहना होगा। यदि हम रूस का साथ छोड़ देंगे, तब रूस-चीन गठजोड़ पूरा हो जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप में रह रहे भारतीयों के साथ रोचक-संवाद किया और उन्हें जिम्मेदारी दी कि वे दुनिया और भारत के बीच सेतु का काम करें। पहली बार यह बात भी सामने आ रही है कि भारत की सॉफ्ट-पावर में बड़ी भूमिका भारतवंशियों की है, जो दुनियाभर में फैले हैं और अच्छी स्थिति में हैं। श्री मोदी की इस यात्रा में जर्मनी, नॉर्डिक देश और फ्रांस तीन महत्वपूर्ण पड़ाव थे। यात्रा के ठीक पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत-यात्रा को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए। आज हम पाते हैं कि, ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटिश-सरकार नए आर्थिक-राजनीतिक समीकरणों से जूझ रही है। इस नई परिस्थिति में भारत को अपनी नई भूमिका को निर्धारित

करते हुए रोडमैप 2030 तैयार करना है। ब्रिटेन के साथ इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप मिलने की उम्मीद है। इसी दौरान यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन दर लेन भी भारत-यात्रा से होकर गई थीं। उनकी यात्रा के दौरान भारत-ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कौंसिल का गठन हुआ है।

इस यात्रा के तीन पड़ावों के अलग-अलग रंग थे। एक अरसे बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला विदेशी दौरा था। तीन दिन के इस दौरे में वे सबसे पहले जर्मनी पहुंचे, फिर डेनमार्क के साथ द्विपक्षीय-वार्ता की और कोपेनहेगन में इंडिया-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में पांच नॉर्डिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ हिस्सा लिया।

भारत और जर्मनी दोनों देशों पर अमेरिका और यूरोप के देशों का दबाव है कि आप रूस से रिश्ते तोड़ें। जर्मनी के भी तमाम हित रूस के साथ जुड़े हैं, इसलिए कई मायनों में भारत की स्थिति वहां समझी जा सकती है। दोनों ही देशों ने हाल के वर्षों तक चीन के साथ रिश्ते बेहतर बनाए और दोनों के रिश्ते अब चीन के साथ टूट रहे हैं। दोनों देशों को चीन से निराशा मिली है। भारत और जर्मनी के बीच कई समझौते हुए, जिनमें साल 2030 तक जर्मनी से हरित ऊर्जा के लिए दस अरब यूरो की मदद मिलना भी शामिल है। दोनों देशों के बीच हुए समझौतों में तकनीकी सहयोग, अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, जैव विविधता को बचाना और कृषि भूमि उपयोग में सुधार करना शामिल हैं। भारत को अगर ईयू के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करना है तो उसमें जर्मनी की अहम भूमिका होगी। नॉर्डिक देश डेनमार्क की प्रधानमंत्री खुद मोदी की अगुवानी करने एयरपोर्ट गईं। ऐसी प्रतीकात्मक बातें महत्वपूर्ण होती हैं। भारत ने अब उन छोटे नॉर्डिक



देशों की तरफ ध्यान दिया है, जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इन पांचों देशों की आबादी केवल 25 लाख है, पर इनकी जीडीपी 1.8 ट्रिलियन है, रूसी जीडीपी से करीब सवा गुना बड़ी। यूक्रेन की तरह ये देश भी अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। यूरोप के ये देश भी अब मान रहे हैं कि भारत महत्वपूर्ण पावर सेंटर है और रूस-चीन गठजोड़ को संतुलित करने में उसकी बड़ी भूमिका है। डेनमार्क और भारत के बीच नौ समझौते हुए। कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा

को बढ़ावा देने के लिए भी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। भारत को अधिक वित्तीय निवेश, तकनीक और कारोबार की जरूरत है। हमें अक्षय-ऊर्जा की जरूरत है। आर्कटिक-क्षेत्र आर्कटिक सागर से जुड़े फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क ने ग्रीन-एनर्जी पर काफी निवेश किया है। हम इन देशों से प्राप्त ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। भारत अंटार्कटिका में सक्रिय है और अब आर्कटिक क्षेत्र में भी अध्ययन करना चाहता है। आर्कटिक-क्षेत्र में 2050 तक बर्फ पूरी तरह पिघलने की संभावना है। दूसरे देशों की तरह भारत की दिलचस्पी भी इस क्षेत्र के संसाधनों पर है। इसके अलावा भारत यहां से होकर गुजरने वाले समुद्री-मार्ग में भी दिलचस्पी रखता है।

नॉर्डिक देशों की आर्कटिक कौंसिल है, जिसमें भारत 2013 से पर्यवेक्षक है। चीन भी आर्कटिक क्षेत्र में अपना प्रभाव काफी तेजी से बढ़ा रहा है। वह अपने बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव को यहां भी लागू करना चाहता है। उसे रूस का भी समर्थन हासिल है, जो इस क्षेत्र के करीब है। नॉर्डिक देश चीन को संतुलित करने के लिए भारत का

साथ दे सकते हैं। श्री मोदी सबसे अंत में पेरिस गए, जहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की। मैक्रों यूरोप के सबसे प्रभावशाली नेता हैं। यूरोपीय परिषद की अध्यक्षता भी इस समय फ्रांस के पास है। हिंद महासागर में फ्रांस की उपस्थिति भी है। यहां उसके द्वीप हैं। रक्षा-तकनीक में वह रूस और अमेरिका के साथ भारत का तीसरा बड़ा सहयोगी देश है। सबसे बड़ी बात है कि करीब तीन दशक से फ्रांस ने अंतरराष्ट्रीय फोरमों पर भारत का साथ दिया है। संरा सुरक्षा परिषद और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भारत की सदस्यता का वह समर्थक है। बहरहाल पेरिस में भी दोनों देशों ने रूस और यूक्रेन पर चर्चा की। यह भी साफ देखा जा सकता है कि रूस की निंदा सिर्फ फ्रांस ने, जबकि भारत ने नहीं की। दोनों देशों ने हिंसा और आक्रामक गतिविधियों को फौरन रोकने की संयुक्त अपील की। 2017 के बाद से मोदी तीन बार फ्रांस की यात्रा कर चुके हैं। 2018 में मैक्रों ने भारत का दौरा किया था। पेरिस में मोदी ने मैक्रों को एक बार फिर भारत यात्रा का न्योता दिया, ताकि अक्षय ऊर्जा और रक्षा तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत किया जा सके। इस लिहाज से मोदी की इस यात्रा से यूरोप में भारत को लेकर एक सकारात्मक माहौल बना है।

इस यात्रा के तीन पड़ावों के अलग-अलग रंग थे। एक अरसे बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला विदेशी दौरा था। तीन दिन के इस दौरे में वे सबसे पहले जर्मनी पहुंचे, फिर डेनमार्क के साथ द्विपक्षीय-वार्ता की और कोपेनहेगन में इंडिया-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में पांच नॉर्डिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ हिस्सा लिया।

यूरोप के उप-क्षेत्र समूचा यूरोप एक जैसा नहीं सोचता और न समूचे यूरोप के हित एक जैसे हैं। यूरोप में उप-क्षेत्रीय हितों को समझने की जरूरत भी है। भारतीय विदेश-नीति के निर्धारकों ने इस बात को समझा है। श्री मोदी की इस यात्रा में जर्मनी, नॉर्डिक देश और फ्रांस तीन महत्वपूर्ण पड़ाव थे। यात्रा के ठीक पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत-यात्रा को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए। ब्रेक्जिट के बाद ब्रिटिश-सरकार नए आर्थिक-राजनीतिक समीकरणों से जूझ रही है। इस नई परिस्थिति में भारत को अपनी नई भूमिका को निर्धारित करते हुए रोडमैप 2030 तैयार करना है। ब्रिटेन के साथ इस साल के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप मिलने की उम्मीद है। इसी दौरान यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन देर लेन भी भारत-यात्रा से होकर गई थीं। उनकी यात्रा के दौरान भारत-ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी कौंसिल का गठन हुआ है। आज मोदी जी की विदेश नीति एवं पहल से विदेशों में रह रहे भारतवंशी वहाँ की सरकार सभी अहलादित विश्व का कल्याण हो के भारतीय संकल्प से अपनों को जोड़ रहे हैं।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति का सर्वोच्च स्थान है। कन्या देवी का स्वरूप होती है पर सामाजिक विकृत सोंच ने परिस्थितियां बदल दी थीं पर आज मोदी-योगी सरकार नारी शक्ति को सशक्त बनाने, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से दिशा बदल दी है। मानव जीवन में विभिन्न अवस्थाएँ होती हैं बाल्यावस्था तथा यौवन के बीच की अवस्था होने के कारण किशोरावस्था नारी के मानसिक, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक विकास की दृष्टि से अत्यन्त परिवर्तनशील होती है। इसीलिए किशोरावस्था नारी के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था मानी गई है। ऐसी स्थिति में मानव संसाधन विकास के उद्देश्य से चलाई जा रही विकासपरक योजनाओं, कार्यक्रमों में किशोरियों को स्थान देना जरूरी है। किशोरियों में आत्मविश्वास, उत्साह एवं आत्मगौरव की भावना में वृद्धि करने के उद्देश्य से उनके पौषाणिक, शैक्षिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार योजनाएं चलाकर उनका विकास कर रही है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश की गरीब परिवार की बालिकाएं, स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं के लिए “उ0प्र0 किशोरी बालिका योजना (एसएजी)” लागू की है। इस योजनान्तर्गत उन्हें जीवन कौशल, शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक-कानूनी मुद्दों तथा मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक करते हुए उनका जीवन स्तर ऊपर उठाया जा रहा है। प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजनान्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष की आयु तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश के समस्त जिलों में कुल 897 परियोजनाओं के 167499 आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा 22290 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इन्हीं आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किशोरियों के सर्वांगीण विकास हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा “उत्तर प्रदेश किशोरी बालिका योजना लागू कर उ0प्र0 की चिन्हित 05 लाख से अधिक किशोरी बालिकाओं को पौष्टिक अनुपूरक आहार उपलब्ध कराया

जा रहा है। इससे उनका शारीरिक व मानसिक विकास हो रहा है।

उत्तर प्रदेश किशोरी बालिका योजनान्तर्गत 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को पोषण आहार के रूप में मोटा अनाज बाजरा, कोदो, रागी, मक्का गेहूं आदि काला चना, अरहर दाल और देशी घी दिया जा रहा है। यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में संचालित है। वहीं प्रदेश के जिलों में मीठा व नमकीन दलिया के अलावा लड्डू, प्रीमिक्स हर माह दिये जा रहे हैं। इसके अलावा आयरन, कैल्सियम व फोलिक एसिड, विटामिन सी आदि की गोलियां भी दी जा रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा “डोर-टू-डोर” ड्राई राशन यथा गेहूं, चावल, दाल, चना, देशी घी एवं स्क्रिड मिल्क पाउडर आदि चिन्हित पात्र किशोरियों को उपलब्ध कराया गया। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों से बालिकाओं को पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रदेश में भारत सरकार के निर्देश के क्रम में चतुर्थ पोषण पखवाड़ा अभियान 21 मार्च से 4 अप्रैल, 2022 तक चलाया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री

योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में स्वस्थ बच्चों की पहचान एवं प्रोत्साहन स्वरूप उत्सव का आयोजन, स्वस्थ भारत के लिए आधुनिक और पारम्परिक प्रथाओं के एकीकरण पर केन्द्रित गतिविधियों का आयोजन करते हुए पोषण पखवाड़ा अभियान चलाया गया जिसमें जन आन्दोलन और सामुदायिक प्रोत्साहन के द्वारा बच्चों, महिलाओं, बालिकाओं के स्वस्थता पर बल दिया गया है। प्रदेश में चलाये गये पोषण अभियान के अंतर्गत लैंगिक संवेदनशीलता और जल प्रबन्धन, एनीमिया प्रबन्धन व रोकथाम तथा जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं, बच्चों के लिए पारम्परिक भोजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनजागरूकता संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया गया है। प्रदेश सरकार की इस योजना से स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकायें लाभान्वित हो रही है।



बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
उ0प्र0 किशोरी बालिका योजना



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत प्रदेश के 27.59 लाख किसानों को रू0 3074.60 करोड़ दी गई क्षतिपूर्ति

प्रदेश सरकार किसानों के हित में अनेकों कल्याणकारी एवं फसलोत्पादन में लाभकारी योजनाएं संचालित कर उनकी आय दोगुनी करने में भरपूर सहयोग दे रही है। किसान वर्ष भर मेहनत कर खेत की जुताई, बुआई, निकाई, सिंचाई एवं खाद डालकर फसल तैयार करता है। फसलों में विशेषकर खरीफ व रबी की फसले होती हैं। खेती किसानों में किसान के पूरे परिवार की मेहनत लगती है। समर्पित एवं कड़ी मेहनत करते हुए परिवार को अच्छे ढंग से पालन पोषण की आशा बनाये रखकर किसान फसल तैयार करता है। किन्तु यदि अधिक वर्षा, आँधी तूफान, पाला, बर्फबारी, ओले, कीट, फसली रोगों, आग आदि जैसी आपदा आ गई और फसल नष्ट हुई, तो किसान की पूरी मेहनत और लागत बरबाद हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान सड़क पर आ जाता है, उसकी समस्त कमाई नष्ट हो जाती है।

देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों की ऐसी स्थितियों/परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आपदा के दौरान नष्ट हुई फसल की क्षतिपूर्ति करने और किसानों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जनवरी, 2016 में शुभारम्भ किया है। इस योजना के लागू होने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। जो किसान ऋण/उधार पैसे लेकर खेती में लगाते थे, उन्हें इस योजना से बड़ा फायदा हो रहा है तथा उनकी आय में स्थायित्व भी आ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारत सरकार की इस योजना को उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर लागू किया है। इस योजना में ऋणी कृषक अनिवार्य रूप से तथा अन्य कृषक स्वैच्छिक आधार पर सम्मिलित किये गये हैं। बीमित राशि को फसल के उत्पादन लागत के बराबर जनपद स्तर पर अधिसूचित किया गया है। सभी फसलों हेतु वास्तविक प्रीमियम दर पर लागू किये गये हैं। प्रीमियम मद में कृषक की देयता को खरीफ फसल में अधिकतम दो प्रतिशत तथा

रबी फसल में अधिकतम 1.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। नकदी व औद्यानिकी फसलों हेतु प्रीमियम मद में कृषक की देयता अधिकतम 05 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। कृषक द्वारा वहन किये जाने वाले प्रीमियर अंश से अधिक व वास्तविक प्रीमियर दर के अंतर की समस्त धनराशि को अनुदान के रूप में केन्द्र व राज्य द्वारा बराबर वहन किया जाता है। प्रदेश के प्रत्येक जनपद में फसल की उत्पादन लागत के अनुरूप बीमित राशि निर्धारित की गई है।

प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सभी इच्छुक एवं जरूरतमंद किसानों तक पहुँचाते हुए क्षतिपूर्ति की धनराशि किसानों को समय से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 के खरीफ 2017 में 25.81 लाख बीमित कृषकों द्वारा 23.83 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया जिसमें से योजना के प्राविधानों के अनुरूप 4.01 लाख कृषकों को रू0 244.86 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। रबी 2017-18 में योजनान्तर्गत 28.39 लाख बीमित कृषकों द्वारा 23.24 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया, जिसमें से 1.88 लाख कृषकों को रू0 129.12 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। वर्ष 2018-19 के खरीफ 2018 में योजनान्तर्गत 31.69 लाख बीमित कृषकों द्वारा 27.41 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया जिसमें से योजना के प्राविधानों के अनुरूप 5.69 लाख कृषकों को रू0 434.27 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। रबी 2018-19 में योजनान्तर्गत 29.66 लाख बीमित कृषकों द्वारा 24.26 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया जिसमें से 0.38 लाख कृषकों को रू0 18.39 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। वर्ष 2019-20 के खरीफ 2019 में योजनान्तर्गत 23.89 लाख बीमित कृषकों द्वारा 18.89 लाख हे0 क्षेत्र में बीमा कराया गया जिसमें 6.28 लाख कृषकों को

रु0 813.88 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। रबी 2019-20 में 23.32 लाख बीमित कृषकों द्वारा 18.09 लाख हे0 क्षेत्र में बीमा कराया गया जिसमें 3.41 लाख कृषकों को रु0 279.50 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।

वर्ष 2020-21 के खरीफ 2020 में योजनान्तर्गत 22.18 लाख बीमित कृषकों द्वारा 16.88 लाख हे0 क्षेत्र में बीमा कराया गया जिसमें से 4.10 लाख कृषकों को रु0 294.80 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। रबी 2020-21 में 19.87 लाख बीमित कृषकों द्वारा 14.77 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया तथा माह मार्च 2022 तक 2.17 लाख कृषकों को रु0 204.93 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। वर्ष 2021-22 के खरीफ 2021 में योजनान्तर्गत 21.60 लाख कृषकों द्वारा 15.61 लाख हे0 क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया तथा मार्च 2022 तक 7.02 लाख कृषकों को रु0 654.85 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। रबी 2021-22 में 19.90 लाख कृषकों द्वारा 14.21 लाख हे0 क्षेत्रफल में बीमित किया गया है। जिसकी क्षतिपूर्ति प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में कुल 281.25 लाख बीमित कृषकों द्वारा 197.19 लाख हे0 क्षेत्र में। फसलों का बीमा कराया गया, जिसमें 27.59 लाख कृषकों को रु0 3074.60 करोड़ क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।

प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है।

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री, श्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि वैश्विक स्तर पर डी0ए0पी0, एन0पी0के0, यूरिया की कीमतों में वृद्धि होने के बाद भी मा0 प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर भारत सरकार, उर्वरक मंत्रालय द्वारा डी0ए0पी0 की कीमत रु0 3851 प्रति 50 कि0ग्रा0 बोरी पर रु0 2501 का अनुदान, एन0पी0के0 (12:32:16) की कीमत रु0 3388 प्रति 50 कि0ग्रा0 बोरी पर रु0 1918 का अनुदान तथा आयातित यूरिया उर्वरक की कीमत रु0 2450 प्रति 45 कि0ग्रा0/बोरी पर रु0 2183.50/- का अनुदान देते हुए देश में उर्वरकों की कीमतों को बढ़ने नहीं दिया गया है।

श्री शाही ने बताया कि वैश्विक बाजार में कोविड-19 एवं रुस, यूक्रेन युद्ध के कारण उर्वरकों की कीमतों में एवं उर्वरकों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले रॉ-मैटेरियल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 के बाद यूरिया उर्वरक की कीमतों में 192 प्रतिषत, डी0ए0पी0 में 195

प्रतिषत, म्यूरेंट आफ पोटाष (एम0ओ0पी0) में 111 प्रतिषत की बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में डी0ए0पी0 उर्वरक रु0 1350/- प्रति बोरी, एन0पी0के0 (12:32:16) रु0 1470/- प्रति बोरी तथा यूरिया रु0 266.50 प्रति बोरी तथा म्यूरेंट ऑफ पोटाष (एम0ओ0पी0) रु0 1700/- प्रति बोरी की दर पर कृषकों के क्रय हेतु उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध है।

कृषि मंत्री ने बताया कि वर्ष 2020-21 में डी0ए0पी0 पर रु0512 तथा मई, 2021 में रु0 1212, माह अक्टूबर, 2021 में रु0 1625 प्रति बोरी अनुदान अनुमन्य था, जिसे माह अप्रैल, 2022 में बढ़ाकर रु0 2501 प्रति बोरी किया गया है। एन0पी0के0 (12:32:16) वर्ष 2020 में रु0 432, माह मई, 2021 में रु0 921, माह अक्टूबर, 2021 में रु0 1019 प्रति बोरी का अनुदान अनुमन्य था, जिसे माह अप्रैल, 2022 में बढ़ाकर रु0 1922 प्रति बोरी किया गया है। इसी प्रकार एस0एस0पी0 उर्वरक पर भी वर्ष, 2020 में रु0 132, माह मई, 2021 में रु0 376 प्रति बोरी का अनुदान अनुमन्य था,

जिसे अप्रैल, 2022 में भी रु0 376 प्रति बोरी ही रखा गया है।

प्रदेश के कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक सुगमतापूर्वक निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने हेतु 01 अप्रैल, 2022 से 31 मई, 2022 तक यूरिया के 8.00 लाख मी0टन लक्ष्य के सापेक्ष 17.11 लाख मी0टन तथा फास्फेटिक (डी0ए0पी0+ एन0पी0के0) 3.25 लाख मी0टन लक्ष्य के सापेक्ष 5.38 लाख मी0टन की उपलब्धता

सुनिश्चित कराई गई है। इस प्रकार खरीफ सीजन हेतु पर्याप्त मात्रा में यूरिया एवं फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता कृषकों हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में की गई है।

श्री शाही ने कहा कि कृषक हित में लिये गये निर्णयों के कारण उर्वरकों के क्रय पर किसान भाईयों को कोई भी अतिरिक्त बोझ नहीं होने दिया गया, जिससे कृषकों को भारी राहत हुई है। कृषकों के हित में सब्सिडी को बढ़ाते हुए अधिकतम विक्रय मूल्य में वृद्धि न करने एवं उर्वरकों के क्रय हेतु कृषकों को भारी राहत दिये जाने के कार्य हेतु प्रदेश के कृषकों की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार किसानों की हर कठिनाई का हरसम्भव निराकरण करने हेतु दृढ़ संकल्पित है।



हमारा देश मातृभाव का देश

मीना चौबे



हमारा देश मातृभाव का देश है। मातृशक्ति अर्थात् त्याग एवं संस्कारों से परिपूरित वह अविरल धारा जिसके वात्सल्यमयी किनारों पर पल बढ़कर किसी भी राष्ट्र की संतानें अपने पराक्रमी एवं प्रगतिशील स्वरूप को प्राप्त कर राष्ट्र को समृद्धशाली लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। हमारे देश में प्रेम, करुणा, ममता, एवं वात्सल्य सृजन संरक्षण, पालन का स्वरूप ही मातृरूप है। भारत के सदर्थ में तो मातृशक्ति प्रत्येक युग में प्रासंगिक रही है। चाहे त्रेता की सीता हो द्वापर की यशोदा हो या कलियुग की पन्नाधाय माँ हो इन सभी रूपों में स्त्री पुरुष का ऐसा पराक्रमी शिल्प गढ़ा जो कालांतर में शौर्य एवं समृद्धि का अद्भुत प्रकाश स्तम्भ बनकर उभरा जो सदियों तक इस देश की पीढ़ियों को मार्गदर्शित करता रहेगा।

ऐसे यूँ तो चितौड़गढ़ को अनेक कारणों से याद किया जाता है उसमें चाहे अपनी लाज एवं देश के स्वाभिमान को बचाये रखने के लिए रानी पद्मावती और उनकी सँगिनियों के संग जौहर गाथा रही हो। मेरे विचार में वह जौहर न होकर राष्ट्रदेव का महायज्ञ था जिसमें विधर्मियों को अपना शरीर न छूने देने की विकट उत्कंठा इतना विराट विचार हमारे अतिरिक्त विश्व की किसी भी सभ्यता के नाम नहीं लिखा गया।

चितौड़गढ़ को ऐसे अनेक घटनाओं से याद किया जाता है ऐसे में मेरा मानना है कि राष्ट्रधर्म की कर्तव्य निष्ठा पर अपने पुत्र का बलिदान करने वाली वीरांगना पन्ना धाय को मातृशक्ति के उच्चतम मान बिंदु पर स्थापित है। उनकी कर्तव्य निष्ठा स्वामिभक्ति और उससे भी बढ़कर

राष्ट्र (चितौड़) की चिंता उन्हें सबसे अलग खड़ा करता है।

मेरा मानना है कि मातृदिवस पर राष्ट्रभक्ति व स्वामिभक्ति का उससे अच्छा उदाहरण कोई और नहीं, वीरों की धरती चितौड़ गढ़ के इतिहास के पन्ने में पन्ना धाय राणा साँगा के पुत्र राणा उदयसिंह की धाय माँ रही। यहां यह कहना समीचीन होगा कि पन्ना धाय किसी राजपरिवार की सदस्य नहीं थीं। अपना सर्वस्व स्वामी को अर्पण करने वाली वीरांगना पन्ना धाय जो कि कमेरी गाँव की जन्मी जिनका नाम राणा साँगा के पुत्र उदयसिंह को माँ के स्थान पर दूध पिलाने के कारण पन्ना 'धाय माँ' के रूप में राजपरिवार में विश्वस्त व प्रतिष्ठित हुई। पन्ना का पुत्र चन्दन और राजकुमार उदयसिंह साथ-साथ बड़े हुए। उदयसिंह को पन्ना ने अपने पुत्र के समान पाला।

पन्नाधाय ने उदयसिंह की माँ कर्मावती के सामूहिक आत्म बलिदान द्वारा स्वर्गारोहण पर बालक की परवरिश करने का दायित्व संभालने का कार्य किया।

चितौड़ का शासक, दासी का पुत्र बनवीर बनना चाहता था। वो राणा के वंशजों को एक-एक कर मार डालता है। बनवीर एक रात महाराजा विक्रमादित्य की हत्या करके उदयसिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ता है एक विश्वस्त सेवक द्वारा पन्ना धाय को इसकी पूर्व सूचना मिल जाती है पन्ना राजवंश और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहकर उदयसिंह को बचाने के लिए उसने उदयसिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाकर उसे झूठी पत्तलों से ढककर एक विश्वास पात्र सेवक के साथ महल से बाहर भेज देती है और बनवीर को चकमा देने के उद्देश्य से अपने पुत्र को उदयसिंह को वहां सुला देती है।

बनवीर रक्तर्जित तलवार लिए उदयसिंह के कक्ष में आता है और उदयसिंह के बारे में पूछता है। पन्ना उदयसिंह के पलंग की ओर संकेत करती है जिस पर उसका अपना पुत्र सोया था। बनवीर पन्ना के पुत्र को उदयसिंह समझकर मार डालता है।

पन्ना अपनी आँखों के सामने अपने पुत्र के वध को अविचलित रूप से बिना आंसू बहाए देखती रही। और

बनवीर के जाने के बाद अपने मृत पुत्र की लाश को चूमकर राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़ती है। एक स्त्री व माँ के रूप में स्वामी भक्ति की ऐसी मिशाल कहीं नहीं मिलती जिसने कि स्वयं के पुत्र का बलिदान स्वामिभक्ति व राष्ट्र रक्षा के किया गया हो।

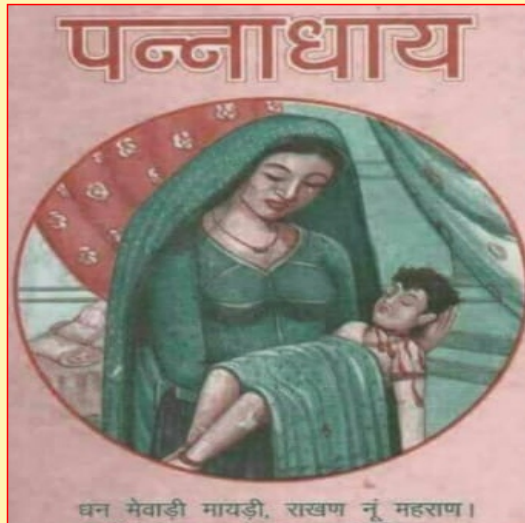
वीरांगना पन्ना धन्य हैं। जिसने अपने कर्तव्य-पूर्ति में अपनी आँखों के तारे पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश को बचाया और इतना ही नहीं करती मेवाड़ के वैधानिक महाराणा पुत्र की मृत्यु के बाद पन्ना उदयसिंह को लेकर बहुत दिनों तक शरण के लिए भटकती रही दुष्ट बनवीर के खतरे के डर से कई राजकुल जिन्हें पन्ना को आश्रय देना चाहिए था, उन्होंने पन्ना को आश्रय नहीं दिया। पन्ना जगह-जगह राजद्रोहियों से बचती, कतराती तथा स्वामिभक्त प्रतीत होने वाले प्रजाजनों के सामने अपने

को जाहिर करती भटकती रहती है और अंततः कुम्भलगढ़ में उसे यह जाने बिना कि उसकी भवितव्यता क्या है शरण मिल जाती है। उदयसिंह किलेदार का भांजा बनकर बड़ा होता है और तेरह वर्ष की आयु में मेवाड़ी उमरावों ने उदयसिंह को अपना राजा स्वीकार कर उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। उदय सिंह 1542 में मेवाड़ के वैधानिक महाराणा बन जाते हैं।

मेवाड़ के इतिहास में जिस गौरव के साथ प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप को याद किया

जाता है, उसी गौरव के साथ पन्ना धाय का नाम भी लिया जाता है, जिसने स्वामीभक्ति को सर्वोपरि मानते हुए अपने पुत्र चन्दन का बलिदान दे दिया। इतिहास में पन्ना धाय का नाम स्वामिभक्ति के शिरमोरों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है।

जिसने अपने स्वामी की प्राण रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया उसी दिन से सिसोदिया कुल वीरांगना के रूप में सम्मान मिल रहा है। अपने स्वामी की प्राण रक्षा के लिए इस तरह का बलिदान इतिहास में पढ़ने को और कहीं नहीं मिलता। धन्य – धन्य है चितौड़ की भूमि धन्य धन्य है भारत भूमि। वीरांगना पन्ना धन्य हैं। जिन्होंने अपने कर्तव्य-पूर्ति में अपनी आँखों के तारे पुत्र का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश को बचाया।



श्री गुरु तेग बहादुर जी

डॉ. चरनजीत कौर



शहीद फारसी का शब्द है। किसी ऊँचे सच्चे उद्देश्य, आदर्श, अधिकार, सत्य परायणता, धर्म या धर्म युद्ध आदि के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देने वाले को शहीद कहते हैं। इतिहास गवाह है कि आध्यात्मिक सत्य की स्थापना के लिए ईसा ने बलिदान दिया। सामाजिक संतोष के लिए पैरिस कमियों ने जीवन की बली दे दी एवं बौद्धिक ज्ञान के लिये सुकरात ने विष का प्याला सहर्ष ग्रहण किया, लेकिन श्री गुरुनानक परम्परा के नौवें वारिस श्री गुरु तेग बहादुर जी ने आध्यात्मिक सत्य, सामाजिक, संतोष एवं बौद्धिक ज्ञान तीनों से ऊपर उठकर एक ऐसे आदर्श के लिए बलिदान दिया जो शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक सम्पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने के लिये था।

यह आत्म सम्मान, आत्म विश्वास एवं आत्मबल को अर्जित करने के लिये था यह किसी एक कौम, धर्म, वर्ग के लिये नहीं वरन् सम्पूर्ण मानवता के लिये था। आपके जीवन की प्रसिद्ध घटना शहादत है तथा संसार के कल्याण हित दिये गये उपदेशों में महत्वपूर्ण है।

भय काहू को देत नेह, ना भय मानत आन।

दोनों से निर्भयता का संकल्प स्पष्ट है।।

शहीद व्यक्ति निर्भय होता है उसके लिये आदर्श शरीर से अधिक महत्वपूर्ण होता है। शरीर मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है। इसे नकारा नहीं जा सकता है, शरीर के माध्यम से ही भौतिक संसार से संबंध स्थापित होता है। उस परमपिता परमेश्वर से जुड़ाव भी शरीर के द्वारा स्थापित होता है। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से सामाजिक जुड़ाव के लिये भी शरीर आवश्यक हैं। बिना शारीरिक ज्ञान के शायद हम प्रकृति के प्रति भी चैतन्य नहीं हो सकते हैं। यह स्वीकारते हुये भी यह नहीं कहा जा सकता है कि शरीर ही जीवन है। मन, बुद्धि भी आवश्यक है, शरीर सांसारिक सुखों की मांग करता है। मन, बुद्धि, ज्ञान, स्वतंत्रता चाहता है। सामाजिक उन्नति के लिये शारीरिक सुख समृद्धि से अधिक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है जो जीवन को उच्चतम कीमत प्रदान करती है लेकिन इसे जीवन का केन्द्र बिन्दु नहीं मानते हैं। गुरुजी शरीर की उपयोगिता को स्वीकारते हुये कहते हैं।

सांसारिक इच्छाओं से उपर उठकर सत्य को खोजें एवं परम् आनन्द की प्राप्ति के लिये प्रेरित करते हुये गुरुजी फरमाते हैं।

**आसा मनसा सगल त्यागे, जग ते रहे निरासा।
मानव यौनि अनमोल है, इसको व्यर्थ में गवाना नहीं है।।**

आप फरमाते हैं

मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गवायो।

“संसार में जीवन की जिम्मेदारियों को निभाते हुये उस परम्परा में मन जोड़ना है,

जग रचना सब झूठ है, जान लेयो रे मीत

कोह नानक थिर न रहे जो बालू की भीत।

बाहर भटकना है अंदर ठहराव है सांसारिक प्राप्ति में बाह्य संघर्ष हैं जो कभी खत्म होने वाली नहीं आन्तरिक यात्रा जैसे उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगी आनन्द की अनुभूति होती जायेगी। प्रसन्नता से उपर आनन्द और अंत में परमानन्द है जो सचखण्ड में पहुँचा देगी। गुरुजी फरमाते हैं वह परम्पिता परमेश्वर हमारे अंदर है, बाहर ढूँढना व्यर्थ है।

काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोही संग समाई।

पुहप मध्य जियो बास बसत है, मुकर माहि जैसे छाई,

तैसे ही ही हरी वसे निरन्तर धट ही खोजो भाई।।

जतन बहुत सुख के लिये, दुःख को किया न कोए।

कोह नानक सुन रे मना, हर भावे सो होए।।

जब ऐसा महसूस हो कि मैं बलहीन हो गया हूँ तब भी परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं जैसे तेंदेए से हाथी की रक्षा की थी।

बलछुटकियों बंधन परे, कछु न होत उपाए।

कोह नानक अब ओट हर, गज जियो हो सहाए।।

आवश्यकता है सम्पूर्ण समर्पण की अटूट विश्वास की आस्था की।

तब हृदय पुकार उठता है—

बल होआ बंधन छुटे, सब किछ होत उपाय।

नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम्ही होत सहाय।।

भारत में मुक्ति से मायने हैं मानवीय आत्मा को शरीर से पृथक हो जाना है। परन्तु गुरु जी के अनुसार मुक्ति अर्थात् सांसारिक दुःखों से निजात पाना है। मानवीय देह दुर्लभ है लेकिन यह दुःखों से घिरी रहती हैं। दुःख मूल का कारण आत्मा एवं शरीर का संयोग है। सम्पूर्ण सुख का साधन वह है जो संयोग को प्राप्त कर ले। इस उपलब्धि का नाम मुक्ति है। यह तभी संभव है जब हम अहंकार आदि दुर्गणों को त्यागकर इस परम्पिता परमेश्वर के नाम का स्मरण कर उसे सही मायने में पहचान लेते हैं।

जेह प्राणी हौमै तजी करता राम पछान

कोह नानक वो मुक्त नर एह मन साची मान।

गुरुजी फरमाते हैं परम् सुख की प्राप्ति के लिये

परमेश्वर की शरण में जाना अति आवश्यक है।

समय बीतता जा रहा है आज और अभी से नाम स्मरण प्रारम्भ कर लें।

अजहूँ समझ कछु बिगरियो नाहिन, भज ले नाम मुरार।

बीत जैं हैं, बीत जैं हैं, जनम अकाज रे।

जो सुख को चाहे सदा सरन राम की लेह।

कोह नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख देह।

दिल्ली के तख्त पर विराजमान औरंगजेब एक पत्थर दिल सुन्नी मुसलमान शासक था वह अपने आप को खुदापरस्त होने का दाहवा करता था, लेकिन खलकत उसके जुल्म का शिकार हो रही थी। उसके मन में इस्लाम की खिदमत का जज्बा, जुनून की हद तक पहुँच गया था। उसने अपने सगे भाईयों का कत्ल करके पिता को कारावास में बंद कर भूखे प्यासे मरने पर मजबूर कर दिया था, वह ललित कलाओं का भी दुश्मन था उसने संगीतकारों का सम्मान तो क्या कहना था वरन् उन पर हर तरह की पाबंदियों लगा रखी थी कोई रियाज नहीं कर सकता था, साजो की मीठी धुन उसे विचलित कर देती थी। उसने अपने राज्य में विशेष अधिकारी नियुक्त किये थे कि जहाँ भी कोई वाद्ययंत्र धुन छेड़ रहे हो उन्हें जला दिया जाये इस तरह यंत्रों के ढेर लगाकर अग्नि के सुपुर्द कर तबाह कर दिया गया। संगीतकार उसके राज्य में भुखमरी के शिकार हो गये। एक कथा काफी प्रचलित है कि औरंगजेब की संगीत के प्रति दुश्मनी से तंग आकर संगीतकारों ने अपने वाद्ययंत्रों को जनाजा तक निकाल दिया था ताकि उसे अपनी भूल का एहसास हो सकें। परन्तु औरंगजेब ने इसके प्रतिकूल यह कहा कि इस संगीत को इतना गहरा दफन करना है कि यह कभी बाहर न आ सकें।

औरंगजेब का केवल एक ही उद्देश्य था कि उसके राज्य में केवल एक ही धर्म का पालन होना चाहिये— वह था इस्लाम। इसकी पूर्ति के लिये वह जायज नजायज का अंतर भूल चुका था उसने हिन्दुओं के मंदिर उनकी पाठशालाओं को बंद कर देने तथा उनके स्थान पर मस्जिदें बना देने का फरमान जारी कर दिये। मंदिर की मूर्तियों से मस्जिदों के पायदान बना दिये गये जितनी भी बेईज्जती की जा सकती थी वह की तदोपरांत हिन्दुओं के तिलक व जनेऊ उतारने शुरू कर दिये गये।

धर्म परिवर्तन का यह कार्य काश्मीर की खूबसूरत प्राकृतिक वादियों से प्रारम्भ किया गया। गैर मुसलमानों की आत्मा दुःख से सिहर उठी। पण्डित कृपाराम की अगवाही में पण्डितों का एक दल सिखों के नौवे गुरु— गुरु तेग बहादुर जी के पास अपने धर्म रक्षा की फरियाद



लेकर 25 मई 1675 को आया। गुरुजी ने कहा औरंगजेब को यह संदेश भेज दीजिए कि यदि गुरु नानक परम्परा के नौवें वारिस दीन कुबूल कर लेंगे तो सारे हिन्दु धर्म परिवर्तन हेतु तैयार हो जायेंगे क्योंकि गुरुजी का मिशन था—

जो सरन आवे, तिस कण्ठ लावै।

मजलूम की बाँह पकड़नी है आपजी फरमाते हैं—

बाँहि जिनां दी पकड़िए, सिर दीजै बाँहि न छोड़िए।

औरंगजेब ने सोचा यह कार्य तो बहुत ही सरल हो गया एक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कहाँ कठिन है ? जोर, जबरदस्ती, लालच बहुत से तरीके हैं जो अपनाए जा सकते हैं। उसने सोचा मेरा सपना साकार होने का समय आ गया है। परन्तु गुरुजी की आत्मिक शक्ति उनके शान्तमयी व्यक्तित्व के प्रति वह अभिनज्ज था। गुरुजी से कहा गया या तो दीन कुबूल कर लो या चमत्कार दिखाओ या फिर मौत के लिए तैयार रहो।

गुरुजी ने मौत को चुना पहली शर्त तो मानी ही नहीं जा सकती थीं क्योंकि धर्म प्रत्येक व्यक्ति का निजी विश्वास अकीदा होता है। यह धर्मिक स्वतंत्रता का विषय है यह स्वअधिकार है इसमें कोई टीका टिप्पणी का प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरी शर्त चमत्कार करामात सिख धर्म के उसूलों के विरुद्ध है कहा गया है। करामात कहिर का नाम चमत्कार दिखाना निम्न स्तर की शोहरत से संबंधित है—

धिग सिखी धिग करामात—

गुरुजी यह जानते थे कि औरंगजेब की असहनीय नीतियों को केवल शहादत द्वारा ही रोका जा सकता है। उनकी आंखों के समक्ष उनके सिखों को शहीद कर दिया गया है— दिल्ली के चौदनी चौक पर 11 नवम्बर 1675 ई. को गुरुजी के पावन शीश को धड़ से अलग कर दिया गया।

शहीद स्थल पर निर्मित सीसगंज साहिब गुरुद्वारा आपकी अद्वितीय शहादत को स्मृति चिन्ह जिस पर लाखें श्रद्धालु आज भी सिर झुकाते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मुगल सलतनत सड़क किनारे गिरे एक सुखे पत्ते की भाँति कहाँ उड़ गई कोई नहीं जानता हैं। शीश धड़ से अलग हो गया लेकिन झुकाया न जा सका—गुरु गोविन्द सिंह जी बचित नाटक में वर्णन करते हैं—

ठीकर फोर दिलीस सिर, प्रभु पुर किया प्यान।

तेग बहादुर सी क्रिया, करी न किन्हू आन

तेग बहादुर के चलत, भयो जगत में सोक

है—है—है सब जग कहो, जै—जै—जै सुर लोक।।

भारत में मुक्ति से मायने हैं मानवीय आत्मा को शरीर से पृथक हो जाना है। परन्तु गुरु जी के अनुसार मुक्ति अर्थात् सांसारिक दुःखों से निजात पाना है। मानवीय देह दुर्लभ है लेकिन यह दुःखों से घिरी रहती हैं। दुःख मूल का कारण आत्मा एवं शरीर का संयोग है। सम्पूर्ण सुख का साधन वह है जो संयोग को प्राप्त कर ले। इस उपलब्धि का नाम मुक्ति है। यह तभी संभव है जब हम अहंकार आदि दुर्गणों को त्यागकर इस परम्पिता परमेश्वर के नाम का स्मरण कर उसे सही मायने में पहचान लेते हैं।

जेह प्राणी हौमे तजी करता राम पछान

कोह नानक वो मुकत नर एह मन साची मान।

गुरुजी फरमाते हैं परम सुख की प्राप्ति के लिये परमेश्वर की शरण में जाना अति आवश्यक है।

समय बीतता जा रहा है आज और अभी से नाम स्मरण प्रारम्भ कर लें।

अजहूँ समझ कछु बिगरियो नाहिन, भज ले नाम मुरार।

बीत जैं हैं, बीत जैं हैं, जनम अकाज रे।

जो सुख को चाहे सदा सरन राम की लेह।

केह नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख देह।

देश की आर्थिक समृद्धि में हुई तेजी से वृद्धि

विपक्ष से विकास की राजनीति अपनाने का आग्रह

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 18 अप्रैल, 2022 को 'देवासियों' के नाम एक पत्र लिखकर कहा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस अवसर पर हमें योजना बनानी होगी कि 2047 में आजादी के सौ वर्ष पूरे होने पर हमारा राष्ट्र कैसा हो। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष से ट्रैक बदलने और विकास की राजनीति को अपनाने का आग्रह किया। हम यहां श्री नड्डा द्वारा लिखे गए पत्र का पूरा पाठ प्रकाशित कर रहे हैं—

भारत विकास यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। यह एक ऐसा

समय है जब हम 'आजादी का अमृत महोत्सव' यानी आजादी का 75वां साल मना रहे हैं। यह आगे बढ़ने का अवसर है, साथ ही हमें इस योजना पर भी काम करना और सोचना होगा कि जब हम 2047 में स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे करें, तो हमारा राष्ट्र कैसा हो।

यह समय ऐसा है जब दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं। 135 करोड़ लोगों का एक राष्ट्र, जिसके बारे में माना जाता था कि यह कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में सबसे कमजोर कड़ी साबित होगा, लेकिन हमने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हम न सिर्फ कोविड-19 सफलतापूर्वक लड़े बल्कि दुनिया को भी हमने मदद पहुंचायी। हमारी अर्थव्यवस्था को खुले और पारदर्शी के रूप में देखा जाता है। हाल के सुधारों ने देश की आर्थिक समृद्धि में जहां तेजी से वृद्धि की है, वहीं हमने गरीबी के आंकड़ों में भी कमी लायी है।

पिछले 8 वर्षों में भारतीय राजनीति में तेजी से बदलाव आया है। अब भारतीय राजनीति में वोट बैंक की राजनीति, विभाजनकारी राजनीति की कोई जगह नहीं बची है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ये देश 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और



आज भारत, राजनीति की दो विशिष्ट शैलियों को देख रहा है— एक तरफ है 'एनडीए' का प्रयास, जो उनके विकास कार्यों में दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ है तुच्छ राजनीति करने वाली पार्टियों का समूह, जो उनके कटु शब्दों में दिखायी दे रही है

दलों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप वोट बैंक की राजनीति के बारे में बात करते हैं, तो आप राजस्थान के करौली में हुई शर्मनाक घटना को क्यों भूल जाते हैं? ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जो इस मुद्दे पर आप खामोश हो जाते

सबका प्रयास' के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, जिससे न केवल हर भारतीय सशक्त हो रहा है बल्कि वो सफलता की नयी उड़ान भी भर रहा है। दुर्भाग्य से विकास की इस राजनीति का उन दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है जिन्हें जनता खारिज कर चुकी है। ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए एक बार फिर वोट बैंक और विभाजनकारी राजनीति की शरण लेना चाह रहे हैं।

आज भारत, राजनीति की दो विशिष्ट शैलियों को देख रहा है— एक तरफ है 'एनडीए' का प्रयास, जो उनके विकास कार्यों में दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ है तुच्छ राजनीति करने वाली पार्टियों का समूह, जो उसके कटु शब्दों में दिखायी दे रही है। पिछले कुछ दिनों में हम इन पार्टियों को एक बार फिर एक साथ आते देख रहे हैं। अब यह साथ मन से है या फिर महज राजनीतिक स्वार्थ है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उन्होंने हमारे देश के मेहनती नागरिकों और उनकी भावनाओं को सीधा ठेस पहुंचाया है।

मैं उन खारिज हो चुके राजनीतिक

हैं?

कौन भूल सकता है नवंबर, 1966 की वो घटना, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद के बाहर बैठे उन हिंदू साधुओं पर गोलियां चलवा दी थी, जिनकी मात्र यही मांग थी कि भारत में गोहत्या पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। राजीव गांधी के उन पीड़ादायी शब्दों को कौन भूल सकता है जब इंदिरा गांधी की मौत के बाद हजारों निर्दोष सिखों के कत्लेआम पर उन्होंने कहा था- “जब एक बड़ा पेड़ गिरता है, तो पृथ्वी हिलती है।”

1969 में गुजरात, मुरादाबाद 1980, भिवंडी 1984, मेरठ 1987, 1980 के दशक में कश्मीर घाटी में हिंदुओं के खिलाफ विभिन्न घटनाएं, 1989 भागलपुर, 1994 हुबली... कांग्रेस शासन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा की सूची लंबी है। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे या 2012 में असम दंगे किस सरकार के तहत हुए थे? इसी तरह, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ सबसे भीषण नरसंहार कांग्रेस के शासन में हुए हैं। यह वही कांग्रेस है, जिसने डॉ. अंबेडकर को संसदीय चुनाव में भी मात दी थी।

तमिलनाडु में, राज्य में सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों ने सिर्फ इस वजह से, भारत के सबसे बड़े गायकों में से एक को अपमानित किया और मौखिक रूप से लिंगिचिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि उनके विचार एक राजनीतिक दल के अनुकूल नहीं थे। क्या यह लोकतांत्रिक है? मतभिन्नता और विचार अलग होते हुए भी साथ रहा जा सकता है, लेकिन अपमान क्यों?

पश्चिम बंगाल और केरल में शर्मनाक राजनीतिक हिंसा और सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर उनकी बार-बार हत्या करना, इस बात की एक झलक पेश करता है कि हमारे देश के कुछ राजनीतिक दल लोकतंत्र को किस नज़रिये से देखते हैं।

महाराष्ट्र में दो कैबिनेट मंत्रियों को भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और असामाजिक तत्वों के साथ संबंधों के

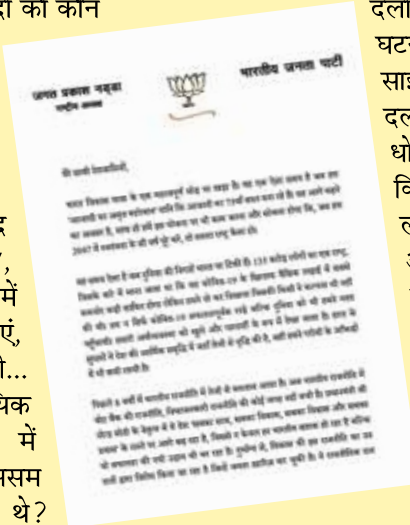
गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। क्या यह एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए चिंताजनक नहीं है कि जिस राज्य में भारत की वित्तीय राजधानी है, वहां एक ऐसा गठबंधन है, जहां शीर्ष कैबिनेट मंत्रियों की ऐसी जबरन वसूली की प्रवृत्ति है?

इसके साथ अब अगली बात पर चलते हैं। यह राजनीतिक दलों के एक चुनिंदा समूह के शर्मनाक आचरण और घटनाओं की सूची है, जो मैंने आप सभी के साथ साझा की है। वोट बैंक की राजनीति करने वाले इन दलों को इस बात का डर सता रहा है कि उनके धोखाधड़ी और करतूतों को व्यापक रूप से उजागर किया जा रहा है कि कैसे दशकों तक उन्होंने आम लोगों को मूर्ख बनाया और तंग किया, किस प्रकार असामाजिक तत्वों को स्वतंत्र रूप से संरक्षण दिया। अब इन तत्वों को देश के कानून के तहत सजा दी जा रही है तो इन असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने वाले लोग घबरा रहे हैं और इस तरह के अनर्गल और अनाप-शनाप आरोप लगा रहे हैं।

हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे वोट बैंक की राजनीति करने वालों के लिए आंखें खोलने वाले होने चाहिए। चुनावी मानचित्र पर भारत के सबसे बड़े राज्य, पश्चिमी तट पर एक तटीय राज्य, पूर्वोत्तर के एक राज्य और एक पहाड़ी राज्य ने भाजपा को शानदार जनादेश दिया है। भाजपा के कारण आज भारत में विकास की राजनीति जोर-शोर से हो रही है और देश में सत्ता-समर्थन की

भावना देखी जा रही है। कई वर्षों बाद राज्यसभा में 100 का आंकड़ा पार करने और यूपी विधान परिषद् में पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली भाजपा पहली पार्टी बन गई। विपक्ष को आत्ममंथन करना चाहिए कि इतने दशकों तक देश पर शासन करने वाली पार्टियां अब इतिहास के हाशिये पर क्यों सिमट कर रह गई हैं।

भारत के युवा अवसर चाहते हैं, बाधा नहीं। वे विकास चाहते हैं, विभाजन नहीं। आज जब सभी धर्मों, सभी आयु समूहों के साथ-साथ जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग गरीबी को हराने और भारत को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक साथ आए हैं, तो मैं विपक्ष से ट्रैक बदलने और विकास की राजनीति को अपनाने का आग्रह करूंगा। इसका श्रेय हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को देते हैं। ■



भारत के युवा अवसर चाहते हैं, बाधा नहीं। वे विकास चाहते हैं, विभाजन नहीं। आज जब सभी धर्मों, सभी आयु समूहों के साथ-साथ जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग गरीबी को हराने और भारत को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक साथ आए हैं, तो मैं विपक्ष से ट्रैक बदलने और विकास की राजनीति को अपनाने का आग्रह करूंगा। इसका श्रेय हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को देते हैं



बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव, जगदीशपुर (बिहार)

जब तक भारत का नाम रहेगा, बाबू कुंवर सिंहजी का नाम अमर रहेगा : अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 23 अप्रैल, 2022 को बिहार के जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव को संबोधित किया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री आर.के. सिंह, श्री नित्यानंद राय, श्री अश्विनी कुमार चौबे और श्री राधामोहन सिंह सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री शाह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज़ादी के 75वें साल में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि इतिहास ने बाबू कुंवर सिंह के साथ अन्याय किया और उनकी वीरता, योग्यता, बलिदान के अनुरूप उन्हें इतिहास में स्थान नहीं दिया गया, लेकिन आज बिहार की जनता ने बाबू जी को श्रद्धांजलि देकर वीर कुंवर सिंह का नाम एक बार फिर इतिहास में अमर करने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि वीर कुंवर सिंहजी एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 80 साल के होने के बावजूद आरा और सासाराम से लेकर अयोध्या तक और वहां से बलिया होते हुए फिर से आरा तक विजयी पताका फहराई। उनके हाथ में गोली लगने से गैंगरीन होने का डर था और इसीलिए उन्होंने खुद अपना हाथ काटकर गंगा में समर्पित करने का साहस कुंवर सिंहजी के सिवा किसी में नहीं हो सकता। उन्होंने जब यहां आकर आजादी का झंडा फहराया उसके 3 दिन बाद वे शहीद हुए।

उन्होंने कहा कि वीर कुंवर सिंहजी ने 1857 और 1858 में बांदा, रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर, सासाराम, गोरखपुर और अयोध्या तक आजादी की अलख जगाने का काम किया था। जब वे यहां अंतिम लड़ाई लड़े, तब गंगा नदी को पार करते हुए हाथ में गोली लगी तो अपना ही हाथ काटकर यहां स्वतंत्र भारत का झंडा फहरा कर उस वीर सपूत ने अंतिम सांस ली। कुंवर सिंह बाबू बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे और उन्होंने पिछड़े और दलितों का कल्याण करने का एक विचार उस जमाने में देश के सामने रखा था।

**वीर कुंवर सिंह
विजयोत्सव
कार्यक्रम में
78,220 तिरंगे एक
साथ लहराकर
भारत ने गिनीज
बुक ऑफ वर्ल्ड
रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। ■**



श्री शाह ने कहा कि जब मैं बच्चा था तो इतिहास के शिक्षक ने बाबू कुंवर सिंहजी के हौसले और वीरता के बारे में बताया था, उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे और आज जब यहां लाखों लोग तिरंगा लेकर बाबू कुंवर सिंहजी को श्रद्धांजलि देने आए हैं तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। एक व्यक्ति कैसा था कि शहीद होने के 163 साल बाद भी लाखों लोग इस चिलचिलाती धूप में उन्हें श्रद्धांजलि देने यहां आए हैं। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मैं सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता की ये पंक्तियां अवश्य सुनाना चाहूंगा— ' इस स्वतंत्रता-महायज्ञ में कई वीरवर आए काम/नाना धुंधूपंत, तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम/अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास-गगन में अमर रहेगे जिनके नाम।' श्री अमित शाह ने कहा कि इतिहास ने बाबू कुंवर सिंहजी के साथ जो भी अन्याय किया हो लेकिन करीब पौने दो सौ साल बाद आज भी जनता में उनके लिए जो भाव है उसे देखकर मैं कह सकता हूं कि जब तक भारत का नाम रहेगा, बाबू कुंवर सिंहजी का नाम हमेशा-हमेशा के लिए अमर रहेगा। ■

अप्रैल-मार्च 2021-22 में भारत का निर्यात अब तक का सर्वाधिक 669.65 अरब अमेरिकी डॉलर हुआ

अप्रैल-मार्च 2021-22 के दौरान भारत के सेवाओं का निर्यात पहली बार लक्षित 250 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ, जो वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 21.31 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है

कें द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 13 अप्रैल को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार भारत का कुल निर्यात (मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज) अप्रैल-मार्च 2021-22 में 669.65 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 34.50 प्रतिशत अधिक है।

गौरतलब है कि अप्रैल-मार्च 2021-22 की अवधि के दौरान व्यापारिक निर्यात 419.65 अरब अमेरिकी डॉलर था, अप्रैल-मार्च 2020-21 की अवधि के दौरान 291.81 अरब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इसमें 43.81 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। अप्रैल-मार्च 2019-20 की तुलना में अप्रैल-मार्च 2021-22 में निर्यात में 33.92 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

अप्रैल-मार्च 2021-22 के दौरान गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न और आभूषण निर्यात 315.11 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो अप्रैल-मार्च 2020-21 में 239.98 अरब अमेरिकी डॉलर के गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न और आभूषण निर्यात में 31.31 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है और अप्रैल-मार्च 2019-20 में हुए 236.17 अरब अमेरिकी डॉलर के गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न और आभूषण निर्यात पर 33.42 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

अप्रैल-मार्च 2021-22 में सेवाओं के निर्यात का अनुमानित मूल्य 250.00 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो अप्रैल-मार्च 2020-21 (206.09 अरब अमेरिकी डॉलर) की तुलना में 21.31 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि और अप्रैल-मार्च 2019-20 (213.19 अरब अमेरिकी डॉलर) की तुलना में 17.27 की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।

अप्रैल-मार्च 2021-22 में सेवाओं के आयात का अनुमानित मूल्य 144.79 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो अप्रैल-मार्च 2020-21 (117.52 अरब अमेरिकी डॉलर) की तुलना में 23.20 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि और अप्रैल-मार्च 2019-20 (128.27 अरब अमेरिकी डॉलर) की तुलना में 12.88 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।

अप्रैल-मार्च 2021-22 के लिए सेवा व्यापार संतुलन का अनुमान 105.21 अरब अमेरिकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-मार्च 2020-21 के 88.57 अरब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 18.80 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल-मार्च 2019-20 (84.92 अरब अमेरिकी डॉलर) की तुलना में अप्रैल-मार्च 2021-22 में सेवाओं ने 23.89 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। ■

‘अटल पेंशन योजना’ के तहत कुल नामांकन 4 करोड़ से अधिक

मार्च, 2022 तक ‘अटल पेंशन योजना’ के तहत कुल नामांकन ने 4.01 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया, जिसमें से 99 लाख से अधिक अटल पेंशन योजना के खाते वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान खोले गए। सभी श्रेणी के बैंकों की सक्रिय भागीदारी के कारण इस योजना को यह जबरदस्त सफलता मिली। लगभग 71 प्रतिशत नामांकन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा, 19 प्रतिशत नामांकन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा, 6 प्रतिशत नामांकन निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा, 3 प्रतिशत नामांकन भुगतान एवं लघु वित्त बैंकों द्वारा किया गया।

31 मार्च, 2022 तक अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन में से लगभग 80 प्रतिशत ग्राहकों ने 1000 रुपये की पेंशन योजना और 13 प्रतिशत ग्राहकों ने 5000 रुपये की पेंशन योजना का विकल्प चुना है। अटल पेंशन योजना के कुल ग्राहकों में से 44 प्रतिशत महिला ग्राहक हैं जबकि 56 प्रतिशत पुरुष ग्राहक हैं। इसके अलावा, अटल पेंशन योजना के कुल ग्राहकों में से 45 प्रतिशत ग्राहकों की आयु 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच है।

उल्लेखनीय है कि अटल पेंशन योजना पीएफआरडीए द्वारा

प्रशासित भारत सरकार की सुनिश्चित पेंशन योजना है। यह योजना भारत के 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के किसी भी नागरिक को बैंक या डाकघर की शाखाओं, जहां उसका बचत बैंक खाता है, के माध्यम से शामिल होने की

अनुमति देती है। इस योजना के तहत एक ग्राहक को उसके योगदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु से 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये प्रति माह तक का न्यूनतम गारंटी पेंशन मिलेगा।

ग्राहक की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा और ग्राहक और उसके जीवनसाथी, दोनों, के निधन पर ग्राहक की 60 वर्ष की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी। ■



केंद्र सरकार ने 2021-22 में खाद्य सब्सिडी के लिए जारी किए 2,94,718 करोड़ रुपये

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत खरीद कार्यों और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत खाद्यान्न के निर्बाध वितरण के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 2,92,419.11 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के मुकाबले डीसीपी और गैर-डीसीपी दोनों गतिविधियों के तहत भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारों को खाद्य सब्सिडी के लिए 2,94,718/- करोड़ रुपये जारी किए हैं।

खाद्य सब्सिडी हेतु दी गई यह राशि 2020-21 के दौरान जारी खाद्य सब्सिडी का लगभग 140% और 2019-20 के दौरान उपलब्ध कराई गई खाद्य सब्सिडी का करीब 267% है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 3,04,879/- करोड़ रुपये के शुद्ध आवंटन के मुकाबले 3,04,361 करोड़ रुपये खर्च करके 99.83% व्यय हासिल किया है।

केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए तत्पर रहता है कि उसकी योजनाओं का लाभ समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों तक पहुंचे। इस मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने अनुसूचित जातियों के लिए लगभग 24,000/- करोड़ रुपये, अनुसूचित जनजातियों हेतु 12,000/- करोड़ रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र को 400/- करोड़ रुपये से अधिक धनराशि जारी की है।

कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत 80 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो की दर से अतिरिक्त खाद्यान्न उनकी मासिक पात्रता के अलावा भी मुफ्त में जारी किया गया है। यह अतिरिक्त आवंटन अप्रैल, 2020 से मार्च, 2022 तक अब तक 5 चरणों में किया गया है।

इसकी शुरुआत के बाद से इस योजना के तहत 2.60 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित वित्तीय खर्च के साथ कुल 758 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न आवंटित किया गया है। पीएमजीकेएवाई को अब सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें लगभग 80,851/- करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय लागत के साथ 244 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का अधिक आवंटन शामिल होगा।

कुल 1175 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न, जिसमें रबी विपणन सत्र 2021-22 के दौरान गेहूं की खरीद और खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में धान का क्रय शामिल है, उससे न्यूनतम समर्थन मूल्य के 2.31 लाख करोड़ रुपये के सीधे भुगतान के साथ 154 लाख से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया है।

भारत सरकार ने चीनी उद्योग का सहयोग करने और चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाबद्ध हस्तक्षेप किए हैं, जिससे किसानों के गन्ना बकाया का भुगतान किया जा सके। इस दिशा में विभिन्न चीनी क्षेत्र की योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता दी गई— चीनी मिलों को चीनी सीजन

2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए सहायता योजना (निर्यात योजनाएं); बफर स्टॉक की तैयारी एवं रखरखाव के लिए योजना (चीनी सीजन 2018-19 में 30 एलएमटी) व (चीनी सीजन 2019-20 में 40 एलएमटी), इथेनॉल उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी और वृद्धि हेतु चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देने के लिए चीनी सब्सिडी की योजना तथा चीनी विकास कोष के तहत ऋण आदि।

उल्लेखनीय है कि एफसीआई और स्टेज एजेंसियों के साथ कुल केंद्रीय पूल भंडारण क्षमता 958.53 लाख मीट्रिक टन है। इसके अलावा, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए गोदामों के निर्माण के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना लागू कर रहा है। ■

खाद्य सब्सिडी हेतु दी गई यह राशि 2020-21 के दौरान जारी खाद्य सब्सिडी का लगभग 140% और 2019-20 के दौरान उपलब्ध कराई गई खाद्य सब्सिडी का करीब 267% है

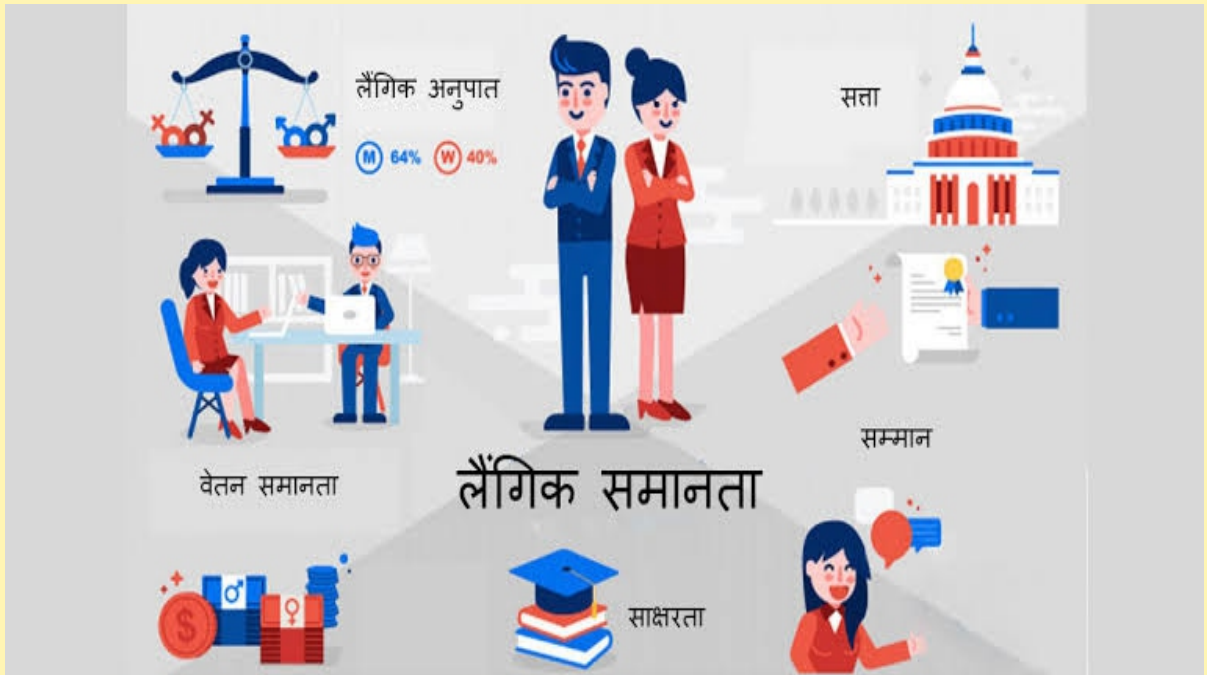
टैंक-रोधी मार्गदर्शित मिसाइल 'हेलीना' का सफल परीक्षण

स्व देश में ही विकसित हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली टैंक-रोधी मार्गदर्शित मिसाइल 'हेलीना' का 11 अप्रैल, 2022 को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना की वैज्ञानिकों की टीमों द्वारा यह परीक्षण उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण ट्रायल्स के हिस्से के रूप में

संयुक्त रूप से आयोजित किया गया।

ये परीक्षण एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एलएच) से किए गए और मिसाइल को नकली टैंक लक्ष्य पर सफलतापूर्वक दागा गया। मिसाइल को एक इन्फ्रारेड इमेजिंग सीकर (आईआईआर) द्वारा निर्देशित किया जाता है जो लॉन्च से पहले काम करता है। यह दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हथियारों में से एक है। ■

बेटा-बेटी के भेदभाव को मिटाना होगा : बेबी रानी मौर्य



कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने कहा कि समाज में लैंगिक असमानता को समाप्त करने का कार्य हम सभी को मिलकर करना है। इसके लिए हम सबको आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि महिलायें आज के समय में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, इसका उदाहरण यहां उपस्थित समस्त महिलायें हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में अपना-अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर रही हैं। श्रीमती मौर्य ने कहा कि महिलाओं के प्रति कहीं भी उत्पीड़न अथवा अत्याचार होता है तो उसे रोकने का कार्य राज्य महिला आयोग करे। पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राज्य महिला आयोग की सदस्य जिन जिलों में जायें वहां पर शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर महिला जनसुनवाई करें। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें। श्रीमती मौर्य ने कहा कि महिलायें तभी सशक्त बनेंगी, जब वह अपने निर्णय स्वयं लेना शुरू कर देंगी। उन्होंने कहा कि संविधान में लैंगिक समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए महिला-पुरुष

,बेटा-बेटी के भेदभाव को मिटाना होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्तीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सरकार द्वारा समेकित प्रयास किये जा रहे हैं। विशिष्ट अतिथि, समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री असीम अरुण ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिशन शक्ति अभियान की बड़ी परिकल्पना तैयार की है। मिशन शक्ति कार्यक्रम में 28 विभाग सम्मिलित किये गये हैं, जो महिला सशक्तीकरण पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के परिणाम स्वरूप महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति काफी जागरूकता आयी है तथा महिलायें पहले से अधिक सशक्त बनी हैं। श्री अरुण ने कहा कि लैंगिक समानता के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। बेटा-बेटी को समान समझे तथा बेटियों को भी बेटों के समान सम्मान व अवसर प्रदान करें। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डा0 भीमराव आम्बेडकर जी ने संविधान में ही महिला एवं पुरुष को समान अधिकार प्रदान किये हैं। महिलाओं के

साथ-साथ किन्नरों को भी समान अधिकार व सम्मान प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किन्नर बोर्ड की स्थापना की गई है।

प्रदेश की राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास पुष्पाहार श्रीमती प्रतिभा शुक्ला ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के हितों के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए नारी सशक्तीकरण अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए नारी शक्ति को आगे आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारा समाज नारी-पुरुष दो पहियों पर खड़ा है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पहियों को समान रूप से मजबूत होना आवश्यक है। श्रीमती शुक्ला ने कहा कि लैंगिक असमानता पर आधारित सामाजिक कुरीतियों तो समाप्त करना होगा।

प्रमुख सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास श्रीमती अनिता मेश्राम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याणनार्थ विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, वन-स्टॉप सेंटर, 181-महिला हेल्पलाइन, बेटा-बचाओ, बेटा-पढ़ाओ, महिला सामर्थ्य योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह आदि योजनाएं संचालित

की जा रही है। इन योजनाओं के व्यापक स्तर पर क्रियान्वयन होने पर महिलाओं की स्थिति मंख सुधार आ रहा है। पिछले पांच वर्षों मंख बाल विवाह का प्रतिशत 21 से घटकर अब 15 प्रतिशत रह गया है।

कार्यक्रम में आये अतिथियों का स्वागत संबोधन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विमला बाथम, उपाध्यक्ष श्रीमती सुषमा सिंह, श्रीमती अंजू चौधरी के द्वारा किया गया। आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विमला बाथम ने उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं को सशक्त व जागरूक करने के लिए किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया



कि मिशन शक्ति के अन्तर्गत मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आयोग की सदस्यों द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में तहसील व ब्लॉक स्तर पर महिला जनसुनवाई व महिला जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए जानकारी प्रदान की जा रही है तथा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति

जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम में यूनिसेफ की सामाजिक नीति विशेषज्ञ श्रीमती पीयूष एंटोनी ने लैंगिक असमानता पर एक लघु फिल्म दिखायी तथा लैंगिक असमानता विषय पर अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम के अंत में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास पुष्पाहार श्रीमती बेबी रानी मौर्या द्वारा राज्य महिला आयोग की सदस्यों को आयोग की तरफ से स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन राज्य महिला आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती अर्चना गहरवार द्वारा किया गया।

हमारा हित

पं. दीनदयाल उपाध्याय

प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख की, हित की, उन्नति की कामना लेकर काम करता है। जहां दुःख हो, वहां से दूर रहना और जहां सुख हो, वहां जाना प्रत्येक व्यक्ति और प्राणी चाहता है। हममें भी सुख और हित की भावना आए, कोई अस्वाभाविक नहीं। इस बात का विचार करना चाहिए कि हमारा हित कहां है। मनुष्य इस छोटी सी बात को समझ नहीं पाता। भगवान् ने यद्यपि मनुष्य को ज्ञानेंद्रियां और कर्मेन्द्रियां दी हैं। ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और कर्मेन्द्रियों के आधार पर जो चाहता है, उसे प्राप्त करते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां कई बार सत् ज्ञान नहीं करवातीं। विशेषकर जब ये ज्ञानेंद्रियां मन के अधीन आ जाती हैं तो यह ज्ञानेंद्रियां मन के चक्कर में पड़कर जैसे मन कहता है, वैसे कार्य करना प्रारंभ करती हैं। मन कहता है, वैसे कार्य करना प्रारंभ करती हैं। मन कहता है, सिनेमा देखने चलो, आंख को कष्ट होने पर भी उसे देखने का कार्य करना पड़ता है। इसलिए मन पर बुद्धि का नियंत्रण जरूरी है।

बुद्धि द्वारा जो बात हितावह होगी, उसे मन से कराना चाहिए। बुद्धि के अनुसार मन को कार्य करने के लिए संस्कार की आवश्यकता है। अब जब व्यक्ति का विचार आता है तो काम करते-करते अपने को अकेला मान चलता है। अपने को सुख मिले, सारी दुनिया उसके हिसाब से चलेगी। यदि कोई ज्योतिषी के पास जाता है और पूछता है, कहो महाराज! हमारे ग्रह-नक्षत्र कैसे हैं? वह चाहता है कि ग्रह नक्षत्र उसकी आशा के अनुकूल चलें और उसके लिए जो हितावह है, उसके अनुसार ही भ्रमण करें। इस तरह अपने को केंद्र बनाकर चलता है। सब लोग इसका विचार करें। भोजन करते समय मेरा भोजन अच्छा हो, यही विचार, समाज जाति को भोजन मिले, इसका विचार नहीं। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र मेरा विचार करे ऐसी अपेक्षा रखता है, पर मैं उनका विचार करूं, ऐसी अपेक्षा कभी रखता नहीं। इसी तरह देश उसका विचार करे ऐसा समझता है, पर वह देश का विचार करे ऐसे अपना कर्तव्य नहीं समझता। यह बात ऐसी ही है, जैसे कोई गाय से दूध तो लेना चाहते हैं, पर उसे खिलाना नहीं चाहते। जैसे किसान खेत से अच्छी फसल तो चाहता है, पर उस खेत में कुछ मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। मैं कुछ भी न करूं तो भी मुझे सभी चीजें मिल जाएं, जिसकी उसे आवश्यकता है। यह कर्म सिद्धांत के विरुद्ध है। अपने यहां कहा गया है, कार्य करो पर फल की अपेक्षा न करो। अब तो

बिना कर्म करे फल की अपेक्षा करते हैं। यह ऐसे ही है, जैसे बिना बीज बोए फल की अपेक्षा करना। कुआं खोदे बिना पानी मिलना। समाज हमें ज्ञान दे, खाना दे, हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और हम समाज को कुछ न दें तो समाज भी आपको कुछ दे न सकेगा। आप समाज की चिंता करें तो समाज आपकी चिंता करेगा। समाज अपने पास कुछ रखता नहीं। हम समाज को मां कहते हैं। उसी तरह जब कोई बेटा अपनी मां को अपनी कमाई लाकर देता है, तब मां स्वयं न खाकर भी अपने बेटे को खिलाती है। इसी तरह समाज भी अपने पास कुछ भी न रखते हुए हमको ही देता है।

यह हिंदू समाज कई सौ वर्षों से देता ही आ रहा है। हमने कभी विचार किया है, क्या कि हम उसे कुछ दे रहे हैं? हमारे पूर्वजों ने समाज को जो दिया है, उसी संचित कोष से आज तक हम प्राप्त कर रहे हैं। हम बाहर दुनिया में जाते हैं तो लोग हमारा सत्कार करते हैं। दो साल पहले जब मैं अमरीका गया, एक सज्जन मिले और उनसे परिचय हुआ तब मैंने कहा, मैं हिंदुस्तान से आया हूं। तो उसने बड़े आनंद से कहा, "You came from the land of Vivekanand." मुझे गौरव का अनुभव हुआ। अपने आचार्य डॉ. रघुवीर' भी कहते थे, जब वे मंगोल देश में गए, तब वहां के बड़े-बड़े लोगों ने उनके चरण स्पर्श कर चरणामृत लिया। उन्होंने कहा, आज हमारा बड़ा सत्भाग्य है। भारत से जो आचार्य आते हैं, उन्होंने हमें ज्ञान दिया है। इस तरह हमारे देश के प्रति इतनी सद्भावना विदेशों में पाई जाती है। यह केवल अपने पूर्वजों द्वारा अपने समर्पण के कारण यह भाव जगा है। ऐसे ही पूर्वजों की कमाई हम खा रहे हैं। आज हम कुछ दे रहे हैं क्या? हमें भी राष्ट्र को कुछ-न-कुछ देने का विचार करना पड़ेगा। इस राष्ट्र का हमारे साथ बड़ा घनिष्ठ संबंध है। हमारा और राष्ट्र का संबंध शरीर और उसके अवयवों में जैसे संबंध होता है, वैसे ही है। हमने नौकरी करते समय कभी यह विचार किया है कि मेरी इस नौकरी का संबंध राष्ट्र के साथ है क्या? हम बाजार में जाकर कोई चीज चार आने में खरीदते हैं और दूसरी चीज तीन आने में। चार आने स्वदेशी है और तीन आनेवाली चीज विदेशी है। यदि हम तीन आने की विदेशी चीज खरीदते हैं तो क्या कभी हमने सोचा है कि तीन आने कहां जाएंगे?

उस तीन आने में से एक आना व्यापारी को मिलेगा और दो



आने बाहर जाएंगे। यदि हम चार आनेवाली देशी चीज खरीदेंगे तो वे चार आने अपने ही देश में रहेंगे। वह पैसे जो हमने वस्तु पर खर्च किए हैं, वे हमी को प्राप्त होंगे। मान लो, हम एक साबुन की टिकिया खरीदते हैं, यदि चार आने में खरीदेंगे तो उसमें से व्यापारी, मजदूर, कारखानादार, तेल आदि कच्चे माल वाले के पास जाएगा। यदि साबुन की टिकिया खरीदने वाला पुस्तक विक्रेता हो तो और यदि उस व्यापारी को जिसने साबुन को टिकिया बेची, जब वह किताब खरीदने जाएगा तब पुस्तक विक्रेता के साबुन पर खर्च किए चार आने प्राप्त होंगे। यदि साबुन की टिकिया विदेशी रही तो कोई विदेशी दूसरा कोई माल खरीदने अपने देश में नहीं आएगा। तब वस्तु पर खर्च किया पैसा विदेशी को ही प्राप्त होगा। अर्थात् हमें उस वस्तु का लाभांश प्राप्त न होगा। हमारा अर्थशास्त्र राष्ट्रीय अर्थशास्त्र होना चाहिए। आज जो राजनीतिक शास्त्र, नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, उसमें व्यक्ति को बड़ा प्रमुख स्थान दिया गया है। जब राष्ट्र की अपेक्षा व्यक्ति को प्रमुखता प्राप्त होती है, तब राष्ट्र अधोगति की ओर जाता है। जैसे एक उदाहरण है, अमीचंद नामक एक धनाढ्य व्यक्ति ने राबर्ट क्लाइव को मदद की थी और ऐसा कहते हैं कि अमीचंद की सहायता के कारण ही राबर्ट क्लाइव प्लासी का युद्ध जीत सका। इस तरह व्यक्ति का लक्ष्य जब अपने तक ही सीमित रहता है, तब हम हर कदम पर राष्ट्र को बेचते चले जाते हैं। आज हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम अमरीका से गेहूं मंगा रहे हैं। इससे हमें अपमान का अनुभव होता है। किसान भी इस विषय में कभी विचार नहीं करता। यदि हम प्रतिदिन के भोजन के समय जो जूठा अन्न छोड़ते हैं, वह न छोड़ें और आधे दिन का उपवास रखें तो जितनी मात्रा में बाहर से अनाज आ रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर आज कोई उस दृष्टि से विचार नहीं करता। यदि कोई उपवास भी रहता हो तो वह निजी स्वार्थ, पुण्य आदि प्राप्ति के लिए करेगा, पर समाज के हेतु एक दिन का उपवास मैं करूंगा, ऐसा कोई विचार करता नहीं। यदि मंदिर भी जाते हैं, तो क्या मांगते हैं? तो कोई पास होने के विषय में मांगता है और कोई भी समाज के संकट निवारण के लिए कुछ मांगता नहीं। इस तरह किसी तरह का भी कार्य करते समय समाज का ध्यान रहता नहीं। यदि किसी को समाज की याद आती भी होगी तो संकट के समय पर आती है।

इस तरह की मुझे एक घटना याद आती है। एक सज्जन थे, उनके घर के सामने बहुत बड़ा मैदान था। उस स्थान पर शाखा लगाने का विचार हुआ और उसके लिए आज्ञा प्राप्त करने हम उस सज्जन के पास गए, तब वे कहने लगे,

पाश्चात्य देशों के लोग समाज और व्यक्ति के बीच संघर्ष मानते हैं। कम्युनिस्ट लोग समाज में वर्ग देखते हैं और उन वर्गों के बीच संघर्ष है, ऐसे मानकर चलते हैं। मुझे एक सज्जन मिले, पूछने पर बताया कि वे समाजवादी हैं। मैंने कहा, आप समाजवादी तो नहीं, पेटवादी हैं या आप किसानवादी, मजदूरवादी हो सकते हैं, पर समाजवादी नहीं हो सकते। कारण, आप मानते हैं कि समाज में वर्ग होते हैं और उन वर्गों में संघर्ष होता है। इस तरह आप किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर आप समाजवादी कैसे कहलाएंगे। जो समग्र समाज का, समाज को वर्गों में विभाजित किए बिना उसका विचार करेगा, वह समाजवादी कहलाएगा

आप हिंदू समाज के संगठन का काम करते हैं? यह तो कम्युनल है, इस काम के लिए हम मैदान नहीं देंगे। थोड़े समय बाद विचार कर कहने लगे, यदि यह मैदान हम आपको देंगे तो उससे हमें क्या लाभ प्राप्त होगा? तो मैंने कहा, हम यह कार्य आपके लाभ के लिए ही कर रहे हैं। तो ये कहने लगे, ऐसी गोलमोल बातें मत करो। एक तो आपका काम कम्यूनल और दूसरा सरकार के विरुद्ध चलता है। इतने पर भी हमें कुछ लाभ न होगा तो हम मैदान क्यों दें? तब मैंने कहा, मैदान किराए पर लेंगे तब हम कम्यूनल नहीं कहलाएंगे क्या? उस समय किराए से मैदान लेने जैसी अपनी स्थिति नहीं थी तो उसे छोड़कर अन्य जगह हमने शाखा प्रारंभ की।

मैदान खाली रहने पर लोग इकट्ठा होते हैं। इस तरह वहां तरह-तरह के लोग इकट्ठा होने लगे। उसमें कुछ मुसलमान गुंडे भी थे, जो वहां जानेवाली स्त्रियों को छेड़ते थे। उस सज्जन ने जाकर उन गुंडों को यह कार्य न करने के लिए कहा। जब वे नहीं माने तब वे मुझसे मिलने आए। कहने लगे, मेरे एक संबंधी संघ में जाते हैं, वे कहते हैं— संघ कार्य बड़ा अच्छा है, मैं चाहता हूँ, आप अपनी शाखा वहां खोलें। मैंने कहा, अब हमारी शाखा तो दूसरी जगह चल रही है। इस समय आवश्यकता नहीं। तो वे बड़े नम्रता के साथ कहने लगे, मेरे से यह जो बड़ा पाप हो गया है, इसे आपको सुधारना ही होगा। मैं सोचने लगा, इस महाशय में इतना परिवर्तन कैसे हुआ। बाद में पता चला कि वे गुंडे उनसे मानते नहीं थे और उन्हें मारने की धमकी भी दी थी। तब वे अपनी शाखा प्रारंभ करने के लिए कहने आए थे। इस तरह मुसीबत जब आती है तब समाज को ज्ञान आता है। इस तरह हम समाज से ज्यादा-ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं।

पाश्चात्य देशों के लोग समाज और व्यक्ति के बीच संघर्ष मानते हैं। कम्युनिस्ट लोग समाज में वर्ग देखते हैं और उन वर्गों के बीच संघर्ष है, ऐसे मानकर चलते हैं। मुझे एक सज्जन मिले, पूछने पर बताया कि वे समाजवादी हैं। मैंने कहा, आप समाजवादी तो नहीं, पेटवादी हैं या आप किसानवादी, मजदूरवादी हो सकते हैं, पर समाजवादी नहीं हो सकते। कारण, आप मानते हैं कि समाज में वर्ग होते हैं और उन वर्गों में संघर्ष होता है। इस तरह आप किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर आप समाजवादी कैसे कहलाएंगे। जो समग्र समाज का, समाज को वर्गों में विभाजित किए बिना उसका विचार करेगा, वह समाजवादी कहलाएगा। ■

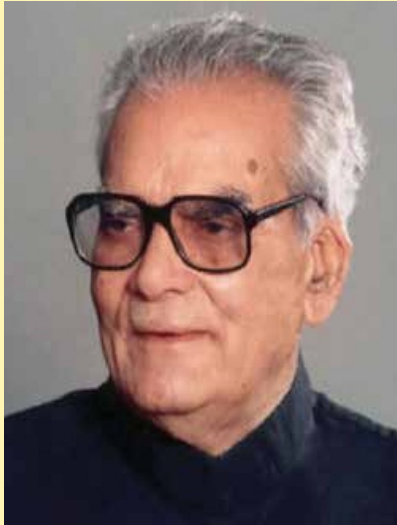
क्रमशः
संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : आंध्र प्रदेश (16 मई, 1965)

कुशल संगठनकर्ता, दक्ष प्रशासक भैरोंसिंह शेखावत

भारत के 11वें उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के राजनीतिक क्षितिज पर लम्बे समय तक छाये रहे। राजस्थान की राजनीति में उनका काफी प्रभाव था। उनके कार्यकर्ताओं ने उन पर एक जोरदार नारा भी दिया, जो इस प्रकार था— “राजस्थान का एक ही सिंह, भैरोंसिंह भैरोंसिंह। यह नारा बहुत लम्बे समय तक गूंजता रहा। भारतीय राजनीति में वह दक्ष और परिपक्व नेता के रूप में जाने जाते थे। उन्हें कुशल प्रशासन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा, श्री भैरोंसिंह शेखावत को राजस्थान में औद्योगिक और आर्थिक विकास के पिता के तौर पर भी जाना जाता है। श्री शेखावत 1952 में विधायक बने। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अनेक सफलताएं अर्जित करते हुए विपक्ष के नेता, फिर मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति बने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत का जन्म 23 अक्टूबर, 1923 को सीकर (राजस्थान) में हुआ। इनके पिता का नाम श्री देवीसिंह और माता श्रीमती बन्ने कंवर थीं। श्री शेखावत ने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा गांव की पाठशाला में प्राप्त की। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा गांव से 30 किलोमीटर दूर स्थित जोबनेर से प्राप्त की। यहां पढ़ने आने के लिए श्री शेखावत को प्रतिदिन पैदल जाना पड़ता था। हाईस्कूल करने के पश्चात् उन्होंने जयपुर के ‘महाराजा कॉलेज’ में दाखिला ले लिया। उन्हें प्रवेश लिए अधिक समय नहीं हुआ था कि पिता का देहांत हो गया। अब शेखावतजी पर परिवार के आठ प्राणियों के भरण-पोषण का भार आ पड़ा। इस कारण उन्हें हल हाथ में लेना पड़ा। उन्होंने पुलिस की नौकरी भी की, लेकिन उसमें मन नहीं रमा और त्यागपत्र देकर वापस खेती करने लगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत जनसंघ के संस्थापक काल से ही जुड़ गये और जनता पार्टी तथा भाजपा की स्थापना में भी उन्होंने



श्री भैरोंसिंह शेखावत जनसंघ के संस्थापक काल से ही जुड़ गये और जनता पार्टी तथा भाजपा की स्थापना में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 1952 में वे 10 रुपये उधार लेकर दाता रामगढ़ से चुनाव के लिए खड़े हुए। इस समय उनका चुनाव चिह्न ‘दीपक’ था। इस चुनाव में उन्हें सफलता मिली और वे विजयी हुए। इस सफलता के बाद उनकी राजनीतिक यात्रा लगातार चलती रही

सक्रिय भूमिका निभाई। वर्ष 1952 में वे 10 रुपये उधार लेकर दाता रामगढ़ से चुनाव के लिए खड़े हुए। इस समय उनका चुनाव चिह्न ‘दीपक’ था। इस चुनाव में उन्हें सफलता मिली और वे विजयी हुए। इस सफलता के बाद उनकी राजनीतिक यात्रा लगातार चलती रही।

वे 10 बार विधायक और 1974 से 1977

तक राज्य सभा के सदस्य रहे। अपने लम्बे राजनीतिक सफर में श्री शेखावत 1977 से 1980, 1990 से 1992 और 1993 से 1998 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे और 2002 में भारत के उपराष्ट्रपति बने। श्री शेखावत का निधन 15 मई, 2010 को हुआ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शिक्षा, बालिकाओं का उत्थान व उनका कल्याण, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और शारीरिक विकलांग लोगों की स्थिति में सुधार पर बल दिया। उनका मुख्य उद्देश्य गरीबों तक अधिकारों का लाभ पहुंचाना था। गरीबों की भलाई के लिए उन्होंने कई योजनाएं क्रियान्वित की, जैसेकि— ‘काम के बदले अनाज योजना’, ‘अंत्योदय योजना’, ‘भामाशाह योजना’, ‘प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम’ आदि। उनके द्वारा शुरू किये गये ‘काम के बदले अनाज योजना’ की मिसाल दी जाती है। श्री शेखावत ने अपने जीवनकाल में ऐसे अनेक काम किये, जिसका आज भी उदाहरण दिया जाता है। सच तो यह है कि अपनी योजनाओं के माध्यम से शेखावत जी ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने का जो सपना देखा था, वह आज साकार हो रहा है।

उन्होंने लोगों की आर्थिक मदद के लिए नई निवेश नीतियां भी शुरू की, जिनमें उद्योगों का विकास, खनन, सड़क और पर्यटन शामिल हैं। उन्होंने हेरिटेज होटल और ग्रामीण पर्यटन जैसी योजनाओं को लागू करने का सिद्धांत दिया, जिससे राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई। इस प्रकार उनके कार्यकाल के दौरान राजस्थान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिति बेहतर रही। दरअसल, आजीवन राष्ट्रहित में काम करने वाले जननेता शेखावतजी गरीबों के सच्चे सहायक थे। उन्होंने कहा कि मैं गरीबों और वंचित तबके के लिए काम करता रहूंगा, ताकि वे अपने मौलिक अधिकारों का गरिमापूर्ण तरीके से इस्तेमाल कर सकें। ■





दसों दिशाओं में जायें...

